



दीन बन्धु सर छोटूराम

जाट

हिन्दी/अंग्रेजी मासिक पत्रिका



लहर

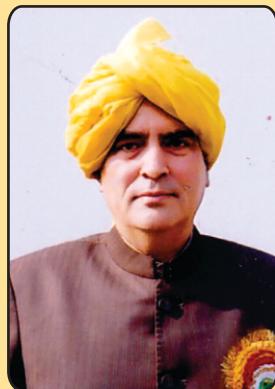
जाट सभा, चण्डीगढ़ के सौजन्य से प्रकाशित

O'KZ17 v d 12

30 Nov Ecj] 2017

eW 5 #i ; s

प्रधान की कलम से



डा. महेन्द्र सिंह मलिक विडंबना है कि एक ही मद पर बार-बार वसूली की जा रही है, वह भी सीधी सरकार द्वारा। भारत में करीब एक लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राज मार्ग हैं, उन पर 394 टोल प्लाजा लगे हुए हैं और दैनिक 51 करोड़ 59 लाख रूपये टोल के रूप में वसूल रहे हैं। केवल वर्ष 2015-2016 में वार्षिक 6700 करोड़ एकत्रित किए गए। यहां यह भी वर्णनीय है कि राष्ट्रीय राज मार्ग भारत के कुल मार्गों का मात्र 2 प्रतिशत है और इन पर 40 प्रतिशत वाहनों की आवाजाई है। दूसरे प्रादेशिक मार्गों जिला मार्गों और ग्रामीण मार्गों पर यह लूट-खसूट स्थानीय सरकारों या स्थानीय छुट्टैया राजनैतिक के प्रश्रय में भी जारी है लेकिन यहां बड़ी धांधली राष्ट्रीय राज मार्गों की सामने आ रही है क्योंकि इन टोल प्लाजों पर समय, पैसा, पैट्रोल और डीजल की बर्बादी होती है।

नया वाहन खरीदी पर 15 वर्ष के लिए रोड़ टैक्स की वसूली की जाती है। पेट्रोल-डीजल की कीमत में हर बार वसूली की जाती है और फिर (बी.ओ.टी.) बिल्ट ऑपरेट और ट्रांसफर के नाम पर शुरू हुआ यह खेल, सड़कों को दो लेन से चार और छः लेन बनाने के नाम पर यात्री सुविधा के नाम यह वसूली एक लाभकारी धंधा बन गया है।

वर्ष 1989 में किसान हितैषी ताऊ देवीलाल ने ट्रैक्टर को किसान का गद्दा तथा कृषि वाहन जान कराधान प्रणाली से छूट दिलवाई थी लेकिन सरकार की पैनी दूषि अब इस पर भी पड़ गई है और ट्रैक्टर को किसानी से निकालकर कमर्शियल वाहनों की श्रेणी में ला खड़ा किया है। अब किसान को ट्रैक्टर की खरीद पर ही 60000 रूपये अधिक देने होंगे उस पर भी रोड़

टैक्स, टोल टैक्स, डीजल की मार और स्थानीय गुंडा टैक्स के नाकों से गुजरना होगा।

रोड़ टैक्स, टोल टैक्स अदा करने के बावजूद भी सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कोई सुध लेने वाला नहीं है और कहीं कोई अपील या दलील भी नहीं है। ट्रैक्टर पर जी.एस.टी. 28 प्रतिशत, कृषि पर 6 प्रतिशत लगेगा। मंडी में मंडी फीस भी बे दे रहे हैं जिसमें ग्रामीण सड़कों का निर्माण निहित है लेकिन उन सड़कों से तो कच्ची गली ठीक थी। टोल प्लाजाओं पर तीन मिनट से अधिक इंतजार करने पर टैक्स अदा ना करने का विधान तो है लेकिन प्लाजाओं पर बैठे नौसिखिए और ठेकेदारों द्वारा बैठाए गए गुंडे-मवाली वाहन चालकों और मालिकों की दुर्दशा कर देते हैं तथा पुलिस अपना हिस्सा वसूलने के चक्र में क्रैई कार्यवाही नहीं करती। कई प्लाजाओं पर निकलने हेतु 20 से 30 मिनट आम बात है। गुरुग्राम टोल प्लाजा इसके लिए विख्यात है, जिस पर मार-पीट और गुंडा गर्दी आम बात हो गई है। अब वाहन चालक अपनी नीयती मान टोल टैक्स की बजाए 'गुंडा टैक्स' देने को मजबूर हैं। किसान दुखी, जवान दुखी, जहान दुखी। सैनिकों को इस कर से छूट का प्रावधान है लेकिन नाकों पर आसीन यहां भी बहाने बाजी कर जैसे तैसे वसूली कर ही लेते हैं जैसे कभी बर्दी नहीं पहनी है तो कभी मूर्मैंट आर्डर दिखाओ। असहाय एवं विरष्ट नागरिक, पीड़ित महिलाएं एवं मासूम बच्चे टोल टैक्स बैरियर पर घंटे तक इंतजार करते हैं।

वर्ष 2017 जनवरी तक 48589 किलोमीटर हाईवे सड़कें निर्माणाधीन हैं तथा 25641 किलोमीटर सड़कें 4 मार्गों से 6 मार्गों हो चुकी हैं। इसके इलावा 9575 किलोमीटर निर्माण प्रक्रिया में हैं तथा 233 किलोमीटर सड़कों के निर्माण हेतु ठेकों की दशा में हैं तथा 13373 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य अलाट किया जा चुका है। अब कुछ आशा की किरण दिखाई देने लगी है कि अब सड़कों के रख-रखाव और सुरक्षा की ओर भी निर्माण के साथ-साथ ध्यान दिया जा सकता है। अब तक एक अनुमान के अनुसार वर्ष भर में वाहन 60000 करोड़ की बर्बादी इन

शुभ सूचना

मैं जाट सभा चण्डीगढ़/पंचकूला की ओर से आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाओं सहित परमपिता परमेश्वर से आपके मगांलमय व सुखद भविष्य की कामना करता हूं। इसके साथ ही आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी कि जाट सभा द्वारा 21 जनवरी 2018 (रविवार) को प्राप्त 11 बजे से 02 बजे तक जाट भवन, 2-बी, सैक्टर 27-ए मध्यमार्ग, चण्डीगढ़ में बंसतपंचमी के शम अवसर पर दीनबन्धु सर छोटूराम की 137वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समारोह के दौरान मेधावी छात्रों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों, सरकारी, अर्ध-सरकारी सेवाओं से सेवा-निवृत होने वाले जाट सभा के आजीवन सदस्यों आदि को नकद पुरस्कार व स्मृति विन्ह भेटकर सम्मानित किया जायेगा। जाट सभा के 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ आजीवन सदस्यों को भी समारोह के दौरान सम्मानित किया जायेगा और ये आजीवन सदस्य अपना नाम व पूरा पता जाट भवन चण्डीगढ़ कार्यालय में भेजने की कृपा करें। आप सभी से सादर निवेदन है कि समारोह में परिवार सहित उपस्थित होकर उत्सव की शोभा बढ़ायें और इस भव्य समारोह के सफल आयोजन के लिये अपने सुझाव भी भेजने की कृपा करें।

इसके अलावा सभी बहनों एवं भाइयों से निवेदन है कि जाट सभा चण्डीगढ़/पंचकूला को स्वेच्छानुसार अनुदान देने की कृपा करें। आप द्वारा दी गई अनुदान राशि को समाज कल्याण के लिये प्रयोग किया जायेगा। जाट सभा को दी जाने वाली अनुदान राशि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी (5) (vi) के तहत पत्रक्रमांक फा.सं. आ आ-2/चण्डी/तक/80जी/ 382/2013-14/01, दिनांक 04-04-2014 द्वारा जीवन पर्यन्त आयकर से मुक्त है।

डा. महेन्द्र सिंह मलिक, आई.पी.एस. (सेवानिवृत)

' KSK I \$ &2 i j

शेष पेज—1

टोल प्लाजाओं पर समय और इंधन की खपत के रूप में हो रही है। भारतवर्ष में करीब एक करोड़ ट्रक और बसें रजिस्टर्ड हैं जिन्हे राष्ट्रीय परमिट मिला हुआ है और केवल औसतन यही वाहन ही वर्ष में प्रति वाहन 4 से 5 लाख रूपये के बल टोल टैक्स अदा करते हैं। इसके बावजूद यह वाहन टाले, नाकों-डाकों पर लंबी-लंबी कतारों में फंसे रहकर इंधन की बर्बादी भी करते हैं। एक सर्वे में बात कही गई थी भारत में जब तक धीमी गति के वाहनों की आवाजाही अलग नहीं होगा तब तक सड़क विस्तार बेकार रहेंगे।

वाहन चालन लागत दिन-ब-दिन बढ़ रही है। लाभांश कम हो रहा है। ऐसे में कहीं हम वाहन उद्योग को तो तहस-नहस नहीं कर रहे हैं? दूसरे देशों से आने वाले पर्यटक यहां से गया दृष्टांत लेकर जाएंगे इसकी किसी को कोई चिंता नहीं है, हर कोई अपनी वसूली में मग्न है। बी.ओ.टी. निर्धारित अवधि पूरी होने के बावजूद 10 वर्ष तक लूट-खसूट की वसूली के बाद भी सरकारी संरक्षण एवं मिली भगत से सड़क पूर्ण का सर्टीफिकेट नहीं दिया जाता। ऐसे कुछेक प्लाजाओं पर पब्लिक आक्रोश के समक्ष एवं मारपीट की घटनाओं के बाद ही छुटकारा मिल पाया है। ऐसी हाल की डेराबस्सी तथा कुराली के पास दो प्लाजाओं पर हो चुका है।

सरकार की पालिसी है कि 60 किलोमीटर के अंदर टोल प्लाजा नहीं बनाया जा सकता लेकिन ऐसे अनेकों उदाहरण इसके विपरीत हैं। चंडीगढ़ से दिल्ली तक नेशनल हाईवे पर घरौंडा से सोनीपत जाने के लिए 60 किलोमीटर के अंदर आने वाले तीन टोल (घरौंडा-115, पानीपत-30, भिगान-65) पर वाहनों से 210 रूपये टोल वसूल किया जाता है। इस रकम के अतिरिक्त जो वाहन चंडीगढ़ से करनाल की तरफ जा रहे हैं उन्हे हरियाणा की सीमा में आने से पहले गांव दप्पड़ की सीमा में स्थित टोल पर 35 रूपये देना पड़ता है। जालंधर से आते हुए शंभू बोर्डर पर 66 किलोमीटर के लिए 70 रूपये देने पड़ते हैं। केवल चंडीगढ़ से दिल्ली के 220 किलोमीटर के रास्ते पर 245 रूपये अदा करना पड़ रहा है। केवल अकेले राजमार्ग पर दैनिक 70 से 80 हजार वाहनों का आना-जाना है। राज्य में एक भी नया हाईवे वास्तव में नहीं बनाया गया है जो भी हाईवे है वह प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, जिसका नाम भी प्राचीन शेर शाह सूरी मार्ग ही विख्यात है और इनका विकास समय के साथ और व्यवसायिक कारणों की आवश्यकता के अनुसार हुआ था। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा न केवल सड़कों पर चलने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन की फीस ली जाती है बल्कि प्रति लीटर के हिसाब से खरीदे गए पैट्रोल व डीजल पर हाईवे सेस भी वसूली किया जाता है। जाहिर है कि इन दोनों का अर्थ है कि जो रकम एकत्रित होती है उससे न केवल रख रखाव होगा बल्कि आवश्यकता अनुसार सड़कों का निर्माण और आधुनिकीकरण भी किया जाएगा किंतु सच्चाई है कि सड़कों को

चौड़ी करने के नाम पर टू-लेन से फेर-लेन और फेर-लेन से छ-लेन करने की घोषणा तो कर दी जाती है परंतु जब वह सड़क बन कर तैयार हाती है तो उसकी रकम सड़क प्रयोग करने वाले वाहनों से वसूल की जाती है। इस प्रकार बिना नई सड़क के निर्माण किए, पुरानी और पारंपरिक सड़क के प्रयोग करने पर भी हर व्यक्ति को टोल देना पड़ता है ताकि उसकी अपग्रेडेशन पर जो खर्च आया है उसे पूरा किया जा सके। वास्तव में हाईवे निर्माण की यह नीति नागरिकों की जेब काटने और टोल चलाने वाली निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई। इससे अनेक विडंबनाएं भी देखने को आई हैं।

इसी प्रकार की स्थिति राज्य के सभी हाईवे पर है। एनएच-52 पर टोलेबल रोड़ की लंबाई लगभग 32 किलोमीटर है परंतु इस पर कार का टोल टैक्स 85 रूपये है। चौथीरीवास टोल जहां टोलेबल रोड़ की लंबाई 40 किलोमीटर है और वहां 40 रूपये और नरवाना टोल जहां पर लंबाई 47 किलोमीटर है वहां 50 रूपये देने पड़ते हैं। नरवाना टोल न केवल नियमों के विरूद्ध है अपितु नेशनल हाईवे अथोरिटी ने 6 सितंबर 2017 को इस टोल को लगाने की स्वीकृति देते हुए नरवाना सब डिविजन को नरवाना गांव दिखाया है ताकि यहां टोल लगाया जा सके। वर्ष 2008 के नियमों के अनुसार नगर परिषद के दायरे में कोई भी टोल नहीं लगाया जा सकता। यह सरासर भ्रष्टाचार का मामला है और हम संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हैं और इस टोल को तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग करते हैं। ज्ञातव्य है कि नरवाना टोल रेलवे स्टेशन से कुल 1.8 किलोमीटर दूर और बस स्टैंड से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है।

एनएच-71 के डाहर टोल पर लगभग 40 किलोमीटर के लिए 85 रूपये, मकड़ौली टोल के लगभग 41 किलोमीटर की लंबाई के लिए 120 रूपये, डीघल टोल के लगभग 27 किलोमीटर की लंबाई के लिए 40 रूपये और गंगायाचा टोल के लगभग 45 किलोमीटर दूरी को तय करने के लिए 70 रूपये देने पड़ते हैं। इस हाईवे पर 153 किलोमीटर दूरी को तय करने के लिए वाहनों से 315 रूपये टोल वसूल किया जाता है। यही हालत एनएच 10 के भी हैं। रोहद टोल की लगभग 56 किलोमीटर की दूरी के लिए 58 रूपये, मदीना कारसून की लगभग 16 किलोमीटर की लंबाई के लिए 55 रूपये, रमैण टोल पर लगभग 63 किलोमीटर के लिए 70 रूपये और लांधरी टोल पर लगभग 42 किलोमीटर दूरी के लिए 70 रूपये का टोल है। इस हाईवे पर 157 किलोमीटर दूरी को तय करने के लिए वाहनों से 253 रूपये टोल वसूल किया जाता है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर मानेसर और पलवल के बीच में जो टोल लागए गए हैं उन पर वाहनों से 70 रूपये टोल वसूला जाता है। इसके अतिरिक्त गुरुग्राम में खेड़की दौला टोल पर 40 रूपये और पंचकुला नगर परिषद के क्षेत्र में चंडी मंदिर टोल पर 29 रूपये वाहनों से वसूल किए जाते हैं।



संगमर में जिले के कालाझार टोल प्लाजा के नजदीक स्थित रोड
पर बना एक अवैध बैरिकेड

पंजाब के संगमर में चल रहे उपरोक्त टोल चित्र से स्पष्ट है कि राष्ट्र में इस प्रकार के अनेकों टोल प्लाजा एक लूट का अपसाना बने हैं। इसी प्रकार का अवैध टोल प्लाजा एन.एच. 1 पर सोनीपत (हरियाणा) में मुरथल के पास लगाया गया है जहां पर टोल बैरिकेड की कोई सुविधा व ढांचा तक नहीं है और साईट पर लोगों से सरेआम टैक्स के नाम पर पैसा वसूल किया जा रहा है। इस कथित टोल प्लाजा को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा एक जनहित याचिका के तहत वर्ष 2008 में जारी की गई आपिसियल नोटिफिकेशन के तहत अवैध घोषित किया गया है। नोटिफिकेशन की धारा 8(1) के अनुसार कोई भी टोल प्लाजा नगर/स्थानीय कस्बे के 10 किलोमीटर के अंदर नहीं लगाया जा सकता और धारा 8(2) के तहत कोई भी टोल प्लाजा पहले से स्थित टोल प्लाजा की 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर नहीं बनाया जा सकता जबकि यहां पर पहले से ही घरोंडा व पानीपत में टोल प्लाजा बने हैं। इसी प्रकार पानीपत में चल रहा टोल प्लाजा अवैध पूरी होने पर भी फलाई ओवर के खर्च के नाम पर चलाया

जा रहा है जबकि सरकार के पास सड़कों व फलाई ओवर के खर्च की पूर्ति हेतु रोड टैक्स व वाहन टैक्स आदि स्रोत पहले से ही उपलब्ध हैं।

यही स्थिति लगभग पूरे देश में है। चाहिए तो यह कि पारंपरित सड़कों के रखरखाव और अपग्रेडेशन के खर्चों को सरकार अपने बजट से बहन करे क्योंकि इस काम के लिए बाहन मालिकों से टैक्स वसूला जाता है। यदि उसके समानांतर भी किसी नई सड़क का निर्माण किया जाता है तो उसे एक्सप्रेसवे या सुपरहाईवे का नाम देकर सरकार अपने आंकलन अनुसार टोल वसूल कर सकती है परंतु नागरिकों के पास हमेशा यह विकल्प होना चाहिए कि वे चाहे तो अपनी पारंपरिक सड़क उपयोग करें और यदि वे चाहें तो नई सड़क का लाभ उठाने के लिए जो भी निर्धारित टोल है उसे दें।

उपरोक्त तथ्यों द्वारा दर्शाए गए आर्थिक आंकड़ों तथा टोल टैक्स की प्रेशानियों व कठिनाईयों से स्पष्ट है कि टोल टैक्स की व्यवस्था पर भारत सरकार द्वारा पुनः गंभीरता से विचार मंथन करके एक नियमित व जनहितकारी नीति बनाने की तुरंत आवश्यकता है जिससे टोल प्लाजाओं पर हो रही जन असुविधाओं व दिन प्रति दिन मार्गों पर घटित हो रहे संकटों को दूर किया जा सके। वर्तमान टोल नीति से तो ऐसा प्रतीत होता है कि टोल टैक्स के लिए न तो समय सारिणी की अवधि निश्चित की गई है और ना ही जन-साधारण की सुरक्षा, हितों, सुविधाओं व समानांतर नियमों का ध्यान रखा गया है।

डा० महेन्द्र सिंह मलिक
आई.पी.एस., सेवानिवृत,
प्रधान जाट सभा चंडीगढ़/पंचकूला एवं
अखिल भारतीय शहीद सम्मान संघर्ष समिति

अमीर और गरीब के बीच भाहराती असामनता

— ज्ञानप्रकाश पिलानियां

यह चिन्ताजनक है कि भारत में अमीरी और गरीबी की खाई ज्यादा हो गई है। अमीर और ज्यादा कमा रहे हैं और गरीबों को काम भी मिल रहा है। सालभर से इकोनॉमी की हालत भले डावांडोल हो देश के बड़े अमीरों की संपत्ति में इजाफा ही हुआ है। अमीरों की आय का आकंलन करने वाली पत्रिका फोर्ब्स की वार्षिक सूची ड्या रिच लिस्ट 2017' में यह जानकारी दी गई है। आर्थिक सुर्सी बाद भी शीर्ष 100 अमीर लोगों की संपत्ति में 26 प्रतिशत इजाफा है। सालभर पहले इनकी संपत्ति 24.31 लाख करोड़ रु थी। अब 13 लाख करोड़ रु हो गई है। यह देश की जीडीपी का करीब 20 प्रतिशत, है। इनमें से टॉप-10 की नेटवर्थ 11.14 लाख करोड़ रु है। यह अमीरों की संपत्ति का 36 प्रतिशत है। फोर्ब्स ने संपत्ति बढ़ने की यह शेयर बाजार को बताया है। सेसेक्स ने साल

भर में 12 प्रतिशत कर्ज दिया है। नेटवर्थ में निजी व पारिवारिक संपत्ति और कंपनियों में हरहोल्डिंग भी शामिल किए गए हैं।

रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी दसवें स्थान पर हैं। उनकी संपत्ति 2.47 लाख करोड़ रु आंकी गई यह पिछले साल से 67 प्रतिशत (99,450 करोड़ रु) ज्यादा सबसे ज्यादा इजाफा उनकी संपत्ति में ही हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2.19 लाख करोड़पति रहते हैं। इनमें एक साल में 19 हजार का इजाफा हुआ है। भारत में अरबपति की संख्या में बढ़ोतारी हो रही है। 'नाइट फ्रैंक ग्लोबल वेल्थ पोर्ट-2016' के अनुसार पिछले 10 साल के दौरान भारत में अरबपतियों की संख्या वैशिक औसत की तुलना में चार गुना से अधिक बढ़ी है। इस दौरान दुनियाभर में अरबपतियों की संख्या में 65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ने 'भारतीयों की आय असमानता, 922–2014: अंग्रेजी राज से अरबपति राज ? टाइटल से रिपोर्ट पेपर में बताया है कि देश के एक फीसदी लोग इतना कमा रहे हैं जितना देश के 22 फीसदी के बराबर हैं। 'हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट इंडिया' के अध्ययन में भी कहा गया है कि भारत में 32 अरबपति हैं, जिनकी कुल प्रोपर्टी एक अरब डॉलर या उससे अधिक है। कुल मिलाकर भारत में अरबपतियों की कुल संपत्ति 392 अरब डॉलर आंकी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नोटबंदी के बाद हाँलाकि देश में अरबपतियों की संख्या में कमी आई है। लेकिन उसकी कुल प्रोपर्टी पिछले साल की तुलना में 16 प्रतिशत बढ़ी है। —हेल्थ ग्रुप के अनुसार, भारत में वेतन वृद्धि में सबसे ज्यादा असमानता है। निचले स्तर पर कर्मचारियों की सैलरी में बहुत कम इजाफा हुआ है। जबकि वरिष्ठ पदों पर लोगों के वेतन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। कंपनियों के सीईओ की आय में तो भारी बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन कर्मचारियों को वेतन कम देते हैं। कुल संपत्ति के लिहाज से भारत दुनिया में छठे नंबर पर है। यह आंकलन 'न्यू वर्ल्ड वेल्थ' ने किया है। संपत्ति दिसंबर 2016 तक की है। भारतीयों की कुल संपत्ति 415 लाख करोड़ रुपये है। छह महीने में यह करीब 10 प्रतिशत बढ़ी है। जून 2016 में कुल संपत्ति 375 लाख करोड़ रुपए थी। देश में 2,64,000 करोड़पति और 95 अरबपति हैं। करोड़पति (मिलिनेयर) से मतलब उन लोगों से है, जिनके पास एक मिलियन डॉलर यानी 6.7 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अरबपति (बिलिनेयर) से मतलब एक बिलियन डॉलर यानी 6,700 करोड़ रुपये संपत्ति वालों से है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष प्रति व्यक्ति आय 1,03,007 रुपये रहने का अनुमान है। यह 2015–16 के 93,292 रुपये से 10.4 प्रतिशत अधिक होगी। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2016–17 में एक लाख रुपये को पार कर जाएगी। ऐसा पहली बार होगा। इसलिए समस्या आय की कमी की नहीं, इसके असमान वितरण की है, जिसका विकाराल विभाजन दिन–प्रतिदिन और गहरा होता जा रहा है।

विश्व बैंक के अनुसार मौजूदा मूल्यों पर भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 1,582 डॉलर है। इस लिहाज से हम गरीब देशों की श्रेणी में आते हैं। मध्य आय वाले देशों की प्रति व्यक्ति जीडीपी 6,000–7,000 डॉलर सालाना है। अगर हम सालाना 8–9 प्रतिशत बढ़तो 9 साल में आमदनी दोगुनी होगी। यानी विश्व औसत तक पहुंचने में 25 साल लगेंगे। मार्गन स्टेनले की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि देश में प्रति व्यक्ति आय काफी कम है। प्रति व्यक्ति 1,700 डॉलर की आय के साथ भारत इस मामले में चीन, रूस, ब्राजील, इंडोनेशिया और फिलीपीन, मैक्सिको और तुर्की जैसे देशों से भी पीछे है। जरूरत है कि सरकार की नई योजनाएं मानवीय जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जाएं, ताकि हरेक सबका विकास में भागीदार बन सके। हाल ही में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी ने अपने एक लेख के माध्यम से बताया है कि भारत में वर्ष 1980 से 2014 के 34 वर्षों के बीच जीडीपी में जो वृद्धि हुई है उसका 66 प्रतिशत ऊपर के 10 प्रतिशत लोगों ने हस्तगतकर

लिया और ऊपर के एक प्रतिशत लोगों के पास विकास का 29 प्रतिशत चला गया।

ज्ञातव्य है कि गरीबी उन्मूलन पर काम करने वाली संस्था 'ऑक्सफैम' की एक रिपोर्ट 'एन इकॉनमी फॉर द 99 परसेंट' के अनुसार, दुनिया की एक फीसदी सबसे अमीर आबादी की संपत्ति का। आंकड़ा बाकी 99 प्रतिशत आबादी की कुल संपत्ति से भी ज्यादा है। यानी यह एक अफसोसजनक सच है कि दुनियाभर में अमीर लगातार अमीर और गरीब ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। खासकर भारत का हाल तो अन्य देशों से भी बुरा है। आर्थिक असमानता की यह खाई हमारे यहां कुछ ज्यादा ही चौड़ी है, जो गांवों से लेकर शहरों तक साफ नजर आती है।

हमारे यहां गरीबी—अमीरी के इस अंतर को पाटना बीती आधी सदी से एक सपना ही बना हुआ है। ये ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि देश में लोगों की आय में असमानता की खाई किस तेजी से बढ़ रही है। हमारे यहां देश की 58 फीसदी संपत्ति पर यहां की महज एक प्रतिशत आबादी का कब्जा है। यह आंकड़ा 50 प्रतिशत के वैशिक आंकड़े से ज्यादा है। इस अध्ययन में यह भी सामने आया है कि भारत के सिर्फ 57 महा धनवान लोगों के पास करीब 15 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है। इतनी ही राशि देश के उन 70 प्रतिशत लोगों के पास है जो आर्थिक हैसियत के हिसाब से निचले पायदान पर खड़े हैं। यही वजह है कि इस रिपोर्ट में ऑक्सफैम ने 'ह्यूमन इकॉनोमी' के निर्माण की वकालत की है, जिससे हरेक व्यक्ति को लाभ मिले, न कि मुठभीभर सुविधा सम्पन्न, लोगों को।

मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में ब्रिक्स देशों में भी भारत की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जीवन प्रत्याशा को छोड़कर मावन विकास की भी कसौटियों में ब्रिक्स देशों की फेहरिस्त में हमारा देश सबसे नीचे है। गौरतलब है कि मानव विकास सूचकांक की रिपोर्टमें प्रति व्यक्ति आय, खपत, रोजगार, कृषोषण, मंहगाई और नागरिकों के सामाजिक मनोवैज्ञानिक हालातों को भी मापने की कोशिश की जाती है। भारत की 36 करोड़ जनता गरीबी की रेखा के नीचे जीवन—यापन को अभिशप्त है। 'क्रेडिट रूस ग्लोबल' की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत में 25.4 प्रतिशत गरीब हैं। परिणामतः यहां एक बड़ी आबादी को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा ही नहीं, आवास एवं भोजन और साफ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी हासिल नहीं हैं। ऐसे में उनका आर्थिक रूप से कमज़ोर होना उन्हें हर तरह से निर्बल बनाता है। साथ ही समाज में मौजूद यह असमानता कई तरह के भेदभाव और शोषण का भी कारण बनाती है। विकास के तमाम दावों के बावजूद यह साबित होता जा रहा है कि आर्थिक उदारीकरण से जुड़ी नीतियां संसार में संपत्ति के न्यायपूर्ण बंटवार में नाकाम साबित हुई हैं। यह व्यवस्था जन सामान्य की खुशहाली और बुनियादी आवश्यकताओं को पुरा करने की बजाय धन के केंद्रीयकरण का जरिया बन रही है।

सरकारी आंकड़े भी दर्शाते हैं कि देश में पूँजी का केंद्रीकरण लोगों के हाथों में हो रहा है तथा आर्थिक असमानता छलागें लगा रही है। देश में कृषि क्षेत्र, जिस पर 60 प्रतिशत से अधिक ग्रामियों

की रोजी रोटी निर्भर है, घाटे में चलता है। कृषि विकास दर इकाई प्रतिशत के आस-पास मंडराती रहती है। जी. डी. पी. में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कम होते-होते 14 प्रतिशत पर पहुंच गई है। देश के विभिन्न भागों में 15000 किसान प्रति वर्ष कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्याएं कर रहे हैं। एक किसान परिवार की मासिक औसत आय 5000 रुपये आंकी जा रही है जबकि 7वें वेतन आयोग के तहत एक चपरासी का मासिक वेतन ही 24,000/- रुपये हैं। वर्ष 1970 में गेहूं का भाव 600 रुपये विटंल था। आज भी मात्र 1450 रुपये है। इस दौरान कर्मचारियों का वेतन 300 गुना बढ़ गया। इससे स्पष्ट होता है कि गरीबी व आर्थिक असमानता में चोली दामन का रिश्ता है।

ध्यातव्य है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था, “मैं ऐसे भारत के लिए कार्य करूँगा, जिसमें गरीब से गरीब व्यक्तियों को भी ऐसा लगे कि भारत उनका अपना देश है— जिसके निर्माण में उनका भी महत्वपूर्ण हाथ है। मैं ऐसे भारत के लिए कार्य करूँगा, जिसमें बसने वाले लागों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग नहीं होगा।” इसके लिए उन्होंने एक “कसौटी” तय की थी— “जब कभी आपके हृदय में संदेह उत्पन्न हो या आप अपने बारे में अत्यधिक विचार करें, तब आप अपने सामने यह कसौटी रखें। अपनी आँखों से देखते हुए सबसे गरीब और सबसे दुर्बल मनुष्य का चेहरा आप याद करें और अपने मन से यह प्रश्न पूछें कि जो कदम उठाने का विचार आप कर रहे हैं, वह उस गरीब और सबसे दुर्बल के लिए उपयोगी सिद्ध होगा या नहीं ? उस कदम से उसे कोई लाभ होगा ? उस कदम से क्या वह अपने जीवन पर और अपने भविष्य पर फिर से अधिकार पर सकेगा ? दूसरे शब्दों में कहूँ तो क्या आपकावह कदम भूखे और

आध्यात्मिक दारिद्रता भोगने वाले लोगों को स्वराज्य की दिशा में ले जाएगा? यक्ष प्रश्न है कि आज, केंद्र एवं राज्य सरकारें कर्मचारी, राजनेता, इस कसौटी पर कितने खरे हैं?

यह घोर विडंबना है कि जब भूखाकिसान रोटी मांगता है तो हम फांस की महारानी मैरी एंटोनेट की तर्ज पर उसे कहते हैं, ‘केक खाओ।’ हमने भी लोगों को ‘भीम’ और ‘आधर पे’ दे दिए, जबकि उनके पास अगले भोजन के लिए नकदी तक नहीं है। भारत की 80 प्रतिशत ग्रामीण आबादी बिना बैंक खातों के जिन्दा है और 95 प्रतिशत भारत आयकर के खाते में ही दर्ज नहीं है। इसी तरह भारत के 6 लाख गावों तक इंटरनेट आज तक नहीं है और 50 प्रतिशत आबादी निरक्षक हैं और स्मार्टफोन, स्मार्ट सिटी और डिजिटल इण्डिया के महत्वाकांक्षी सपनों से वंचित है। यहां तक कि देश की अधिकांश आबादी अशिक्षा, बीमारी, कुपोषण और बेरोजगारी से पीड़ित है।

यह एक त्रासदी है कि आज मुल्क दो हिस्सों में बंटा है— गरीब भारत एवं अमीर इण्डिया। अदाई दशकों के उदारीकरण के मंथन का सारा अमृत इंडिया के हिस्से में जा रहा है। सारा विष भारत को पीना पड़ रहा है। आज एक छोटा सा वर्ग लगातार खराब होती जा रही नारी है। मुल्क का सताधारी परिकथा रचने में जुटा है। पर भारत में गरीबी, भूखमरी और कुपोषण का अंदेरा है, उसकी कोई नामलेवा ही नहीं। क्रोनी-कपीटलिज्म हावी, दलालों का बोलबाला है। देश में 57 लोग बैंकों का 85 हजार करोड़ रुपये कर्ज लिया। इन 57 डिफॉल्टरों के पास 85 हजार करोड़ रु. फंसे हैं। ये चिन्ताजनक हालात सुधारने के लिए ‘समावेशी-विकास’ समय की मांग है।

भारतीय किसान पार्टी के गठन की प्रभातवेला

— सूरजभान दहिया

भावना बनी रही तो उस क्षेत्र में अमेरिका के हित खतरे में पड़ सकते हैं। शास्त्री जी ने एक्टर मनोजकुमार को बुलाकर कहा — मनोज देश के किसान की कृतज्ञता को आप सिनेमा के माध्यम से राष्ट्र के सामने रखो। फिल्म ‘उपकार’ बनी और एक सन्देश भारतीयों के पास पहुंचा— “अन्न के मामले में किसान का देश को आत्म निर्भर बनाने का पवित्र दृढ़ संकल्प।”

भारत में 1960 के दशक में ‘हरित क्रांति का किसान ने’ सूचीपात लिया और भारत को अन्न के मामले में आत्म निर्भर होने का गौरव दिला दिया। परन्तु यह कैसी विडंबना है कि किसी भी राष्ट्रीय समारोह में यह आभास नहीं होता कि हम किसान संस्कृति के पालक हैं। हमारी संस्कृति कृषि से जरूर उपजी है परन्तु कृषि हमारी प्राथमिकता से गायब है। अन्न दाता किसान अपनी आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या का रास्ता अपनाए यह भारत की इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है। किसान चम्पारण सत्याग्रह जिसके द्वारा मोहनदास कर्म चन्द गांधी ‘महात्मा बने का यह शताब्दी वर्ष है। इसलिए कृषि प्रधान देश भारत में लोकतन्त्र की एक नई आवाज ‘भारतीय किसान पार्टी’ का अस्तित्व में आना सामयिक है। सूखा,

भूखमरी, किसान आत्महत्या, भू-हथियाना, ग्रामीण शोषण इत्यादि ज्वलंत मुदे इस पार्टी के गठन हेतु जमीन तैयार कर चुके हैं, बस सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है।

जो इतिहास को भूला देते हैं, वे इतिहास नहीं रख सकते हैं। भारत में जब-जब परिवर्तन का बिगुल बजा है। उसके नायक सदैव किसान रहे हैं। दुःख इस बात का है कि आजाद भारत में किसान इतिहास को दफना दिया गया है। अभी-अभी एक सर्व हुआ है जिसमें यह पाया गया है कि हमारे समाचार पत्र सिर्फ 4 प्रतिशत कवरेज कृषि को देते हैं और 2070 ग्रामीण परिवेश को हमे क्यों 60-70 करोड़ किसानों की आवाज सुनाई नहीं देती? क्योंकि लोकतन्त्र में इतने बड़े समुदाय को राजनैतिक, आर्थिक, प्रशासनिक एवं ऐतिहासिक क्षेत्रों में दबाकर रखा जा रहा है। हम लोकतन्त्र हैं, वोट हमारे और राज तुम्हारा, यह घोर अन्याय है। यह अलोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतन्त्रता के नाम पर यह मानवीय मूल्यों का हनन है, अब यह षडयन्त्र आगे नहीं चलने वाला।

उपरोक्त षडयन्त्र को गम्भीरता से समझना चाहिये। हमारे गणतंत्र स्वाधीन होने का संघर्ष 1857 से शुरू हुआ था। वैसे हमारे गांव तो लघुगणतंत्र थे ही, जहा राजा नहीं जन शासक होता था। यह व्यवस्था चौपाल में बैठक सब की सहमति से सचांलित होती थी और इन्हीं से एक प्रभावी खाप परम्परा बनी। अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध खापों ने जगह-जगह विचार विमर्श करके 1857 में एक जन आन्दोलन चलाकर अपनी नियति का स्वयं निर्धारण करने का निर्णय लिया। हल उठे, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा, लालकिले पर खाप परम्परा परिभाषित हुई—“खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, अन्न अवाम का”। विश्व इतिहास में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध आज तक का यह सबसे बड़ा और अतिशक्तिशाली किसान संघर्ष स्वीकार किया। इस संग्राम में भारत की कुल जनसंख्या के 7 प्रतिशत ने अपने देश की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर किया। यद्यपि ब्रिटिश हकूमत की बड़ी ताकत और अनेक देशी रियासतों, दलालों व चाटूकारों की साजिश के आगे भले ही उस वक्त अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा लेकिन कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद यहां के किसान क्रांतिकारियों ने देश में स्वाधीनता, राष्ट्रीय और जातीय एकता की एक ऐसी मशाल जला दी, जो बाद के संघर्ष का लगातार मार्गदर्शन करती रही। आश्चर्य है कि इस इतिहास को पाठ्य क्रमों से क्यों ओङ्गल कर दिया समज नहीं आता।

अंग्रेजों को किसान शक्ति का उस संग्राम से अहसास हुआ और उन्होंने किसानों के विरुद्ध अनेक हथकंडे अपनाकर किसान की कमर तोड़ दी। किसान के गणतंत्र गांवों की काश्तकारी और दस्तकारी को अंग्रेजों ने तहस-नहस कर डाला। किसान को इस संकट से निकालने के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। बीसवीं सदी के आरम्भ में उतरी भारत में एक अलौकिक शक्ति किसानों के बीच चौ. छोटूराम के रूप में आई 75 वर्ष से पिछे रहे किसान की पीड़ा को उन्होंने एक जेहाद के रूप में राजनीतिक, मीडिया व प्रशासन के समुख पटल पर रखी। इसके द्वारा किसान ने भी सुस्ती तोड़ी, अंगड़ाई ली और चौ. छोटूराम के साथ खड़े हो गए। किसान को नरक की जिंदगी से निकालने के लिए पहले कांग्रेस

के राजनीतिक मंच उन्होंने तलाशा, अंग्रेजों के काले कानूनों को उन्होंने चुनौती देकर ब्रिटिश सरकार को ललकारा व सेठ-साहूकारों के कर्जों के हथ्यों को तोड़ने का बीड़ा उठाया। चाहे कांग्रेसी हो, चाहे अंग्रेज अफसर हो, चाहे सूदखोर हो सभी तो चौ. छोटूराम के कटटर विरोधी हो गये। चौ. छोटूराम अकेले पड़ गये, पर अविचलित रहे। उन्होंने अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु आंधियों, तूफानों व ज्वार भाटा को ललकारा और किसान शोषण मुक्ति की एक संघर्ष पूर्ण इबाटत लिख दी जिसमें वैचारिक गहनता, स्पष्टता, मानवता और प्रगतिवादी कर्मठता थी। सन् 1923 में उन्होंने एक नई राजनीति को परिभाषित किया— किसानों की राजनीति। उस राजनीति का साफ मतलब था कि जिनके हक मारे गए हैं। वे उन्हें गिरें जिनका शोषण हो रहा है। और जो अर्थ के कारण पिछड़े हुए हैं, उन्हें उससे मुक्त कराया जाए तथा उन में नवजीवनीय मूल्यों के प्रति आस्था जागृत की जाए। फजले हुसैन के साथ मिलकर चौ. छोटूराम ने पंजाब में उपरोक्त विचारधारा को लेकर एक नई राजनैतिक पार्टी राष्ट्रीय यूनियनिष्ट पार्टी बनाई। यह एक किसान हितैषी पार्टी थी, इसलिए यह जमीदारा पार्टी के नाम से ही लोकप्रिय हुई।

जमीदारा पार्टी का गठन जाति ग्रस्त मानसिकता से परे और धर्म उन्माद से ऊपर रोजी-रोटी की लडाई के लिए एक साहसिक राजनैतिक नया प्रयोग था जो गहन सोच की दार्शनिकता पर शोषक और शोषित का द्वन्द्व था। उसने थोड़े ही समय में पंजाब की आर्थिक राजनीतिक शैक्षणिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। कांग्रेस व मुस्लिम लीग जैसी राष्ट्रीय पार्टी उस पार्टी के सामने पंजाब में अपना वजूद खो बैठी। कायदे आजम जिन्नाह व पंडित जवाहरलालनेहरू चौधरी छोटूराम के सामने पंजाब में असाधाय दिखे। 1935 के एक्ट के अनुसार पंजाब उसेम्बली के चुनाव 1937 में हुए। जमीदारा पार्टी को 175 सीटों में से 101 सीट मिली, कांग्रेस को 20, सीटें मिली। जमीदारा पार्टी की पंजाब में सरकार बनी तथा चौधरी छोटूराम ने चन्द वर्षों में 30-40 कानून बनाकर पंजाब में किसानों को कर्जों से मुक्त करा दिया। गिरवी रखी भूमि किसानों को वापस मिली, किसानों को उन्नत खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा गांधी जी के रामराज्य के सपने को आगे बढ़ाया।

पंजाब के किसान ने नए सूरज को उगते देखा और वह अनायस बसन्त पंचमी महोत्सव पर समझूम उठा। विरोधी पार्टियों ने चौ. छोटूराम पर तीखे प्रहार करते हुए कहा यह सरकार पंजाब की सरकार नहीं है, बल्कि जमीदारों की सरकार है।” चौ. छोटूराम ने सहर्ष विरोधी की दलीलों को स्वीकार किया और कहा कि आज बेशक पंजाब में किसानों की सरकार है कल भारत में भी किसान राज करेगा। इतिहास के समीक्षक अब लिखते हैं, “बीसवीं सदी का पूर्वाधि विश्व की तीन महान क्रान्तियों का युग था और तीनों क्रांतियां किसान से संबंधित थीं— रस्सकांति, चीन क्रांति और पंजाब की मुक्ति क्रांति। पहली दो क्रांतियों में अपार रक्तबहा लेकिन और माओं विश्वख्याति पा गये, चौधरी छोटूराम की मुक्तिक्रांति रक्तहीन थी और दोनों क्रांतियों से कही अधिक कारार रही।” आश्चर्य होता है कि इस क्रांति की उपलब्धियों को भावी पीढ़ी की जानकारी हेतु ओङ्गल क्यों रखा है? क्यों चौ. छोटूराम के व्यक्तित्व को किसान हितैषी विभूतियों—

गांधी जी, सरदारपटेल व तिलक की भाँति पढ़ा नहीं जाता ? कदाचित शासक पार्टियां भारत में गांधी जी के हिन्दुस्वराज (किसानराज) के सपने को पूरा करने से हिच किचाती रही हैं, पर इतिहास की पुनरावति जरूर होती है। कोई छोटूराम जरूर अवतरित होगा और पंजाब की भाँति भारत में भी एक किसान का शासन होगा।

चौ. छोटूराम 1945 में चल बसे और भारत 1947 में आजाद हुआ। इन घटनाओं ने पंजाब की जमीदारा पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। आजाद भारत में किसान संबंधित परियोजनाएं हाशिए में चली गई। किसान पर संकट के बादल गहराते चले गये, राजनीतिक पटल पर न गांधी जी थे, न पटेल और न चौ. छोटूराम। फलस्वरूप किसान अपने आपको असहाय महसूस करने लगा। चौ. चरणसिंह ने ग्रामीण भारत की समस्याओं को राजनीतिक मुदा बनाकर किसानों की रहनुमाई का दायित्व उठाया। इस सन्दर्भ में चौ. चरणसिंह इंडिया बनाम भारत की बात सामने रखी। चौधरी चरणसिंह ने कहा कि किसान को विकास प्रक्रिया में उपेक्षित कर दिया गया है, इसलिए किसान आर्थिक दबाव में आ गया है। इससे राजनीतिक सवाल खड़े हो गए हैं। अनेक अर्थशास्त्रियों ने चौधरी साहिब की बात में सच्चाई लगी। महाराष्ट्र में शरद जोशी ने इसे ज्वलंत मुद्दा बनाया तो उत्तरी भारत में महेन्द्र सिंह टिकैत ने इसे लुटेरों और कमरे के बीच लड़ाई करा दिया अब प्रान्तीय व राष्ट्रीय स्तर पर किसान नेतृत्व की शून्यता है इसलिए किसान शोषण अब भी चरम सीमा पर है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां किसान हित में नहीं दीखती यही कारण है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशे क्रियान्वित नहीं हो रही हैं।

हमें किसान की पीड़ा को समझफना होगा। किसान की आर्थिक तंगी को हमें अनुभव करना होगा। वह बजुबान है, उसे आवाज देनी होगी। राष्ट्र को बताना होगा कि कृषि प्रधान देश भारत में 58 फीसदी किसान क्यों भूखे सोते हैं ? एक किसान परिवार की प्रतिमास आय अब ज्यादा से ज्यादा 6000 रुपये लगाए गए अनुमान के अनुसार राष्ट्रीय सेम्प्ल द्वारा है जब कि एक सरकारी मुलाजिम का सातवें वेतन आयोग के बाद कम से कम 18000 रुपये वेतन कर दि गया है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि आजादी के बाद किसान ने भीषण गर्भी, भीषण सर्दी, भीषण वर्षा व भीषण सूखे को फेलकर भी गेहूं का उत्पादन सात गुना, मक्का का चार गुना और चावल का तिगुना कर दिया हैं इसके बावजूद किसान क्यों नरक की जिदंगी बिता रहे हैं? आज सामान्य किसान और खेतिहार मजदूर की झोपड़ी में न लक्ष्मी (समद्वि) और न सरस्वती (शिक्षा) हाँ, बेकारी उसके दरवाजे पर निरन्तर दस्तक दे रही है। ऐसी रियासतों में यह प्रश्न मन में बार बार उठता है कि हरित क्रांति (अनाज में निर्भरता रखेत क्रांति) (दूध में आत्म निर्भरता) और नीभी क्रांति (मछली पालन में निर्भरता) का अमृत कुंउ कौने ले भागां हैं? कहा और क्यों अटक गई – ग्राम विकास की हरहराती गंगा?

देश में अपी तक किसान समृद्धि नीति नहीं बनी है। यहां कृषि नीति जो भी बनी है वह प्रायः ओघांगिक हितों की मातहती करने के उद्देश्य से ही सूत्रबद्ध की गई। गांधी के बताए गए उपायों द्वारा प्रत्येक ग्राम को स्वावलम्बी ईकाई बनाने का प्रयास किया जाना था, जो नहीं हुआ। ग्राम रोजगार पर काफी जोर दिया जाना था। उल्टा हुआ

शहरीकरण पर जोर दिया गया अब भी दिखा जा रहा है। शहरों की तरफ पलतायन घंवंसकारी है इसलिए गांव/शहरा की खाई घटने की बजाए और चौड़ी होती जा रही है। क्या बापू के हिन्दू स्वराज की यहीं कल्पना थी?

हमारे देश की आर्थिक नीति विदेशी शक्तियां तय करती हैं। विश्व बैंक का जोर है। भारत के 40 करोड़ ग्रामीण शहरों में आकर बसे जो हमारी संस्कृति पर धावा है। विदेशी शक्तियां हमारी खेती को तबाह करने पर उतारू हैं। वहां की कॉरपोरेट कम्पनियों को पता है कि भारत की रीढ़ किसान है, उसे नष्ट कर दो। भारत में आर्थिक गुलामी स्वतः दस्तक दे देगी। विदर्भ में सतंरा 3 रु किलो खरीदा जाता है, पंजाब से आलू एक रुपये प्रति किलो लिया जाता है। कभी-कभी तो वहां किसान सड़क पर बोर्ड लगा देता है— “बोरा लाइए मुत आलू ले जाइए”। जब किसान से कृषि उत्पाद व्यापारियों के पास चला जाता है तो टमाटर व याज 100 रु प्रति किलो बाजार में बिकता है। उधर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि किसान पर इन्कम टैक्स लगाना चाहिए — किसान मालामाल है, फूड सब्जी खत्म होनी चाहिए। न्यूनतम समर्थ मूल प्रक्रिया बंद होनी चाहिये, सामने की बात यह है कि किसान को उसका आर्थिक हक क्यों नहीं मिलता? जरा सोचिए, 1970 में गेहूं का समर्थन मूल्य 76 रु प्रति किंविट था और 2016 में यह 1525 रु— कितना मालामाल हो गया किसान इससे और तथ्यों का भी अवलोकन कीजिए — 2004 से 2015 तक कारपोरेट जगत को भारत सरकार ने 42 लाख करोड़ की राहत दी जबकि किसान सभिंडी सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए की थी। किसान नेता महेन्द्र सिंह टिकैत कहते थे— “हमारे देश में पूँजी पति सता से रिश्ता जोड़कर किसानों का लहू चूसते हैं। अपने हाड़-मांस गलाकर खेती करने वाला किसान तो हमेशा सूने आकाश की ओर ताका करता है।

आज कृषि क्षेत्र में पूर्ण परिवर्तन लाने की अनिवार्यता है। यह क्या माजरा है कि सरसों उगाने वाला किसान भूख से मर जाता है। सरसों से तेल निकालने वाला मिल मालिक चन्द वर्षा में ही करोड़पति बन जाता है। नीती बनने से प्रत्येक किसान का गठन एक अपरिहार्य न्यूनतम स्तर प्राप्त कर सके, कृषि को सम्मानित व्यवसाय का रूप मिले तथा देश के विकास की भावी दिशाएं गांव व खेत-खलिहान द्वारा तय हो। भारत में कृषि राष्ट्रीय जीवन और अर्थव्यवस्था का मूल भूत आधार रहे। इसके लिये अब यह जरूरी हो गया है कि देश के 60-70 करोड़ किसान अपनी नियति का स्वयं निर्धारण करें और अपनी आवाज एक मंच पर आकर अपनी राजनीतिक शक्ति का परिचय दें।

मानते हैं कि इतिहास दोहराता है। याद करें आज से कोई सौ साल पहले 1923 में जब चौ. छोटूराम ने जमीदारा पार्टी बनाई थी तो उन्होंने उद्घोषणा की थी— “यह पार्टी उस ग्रामीण शक्ति को परिभाषित करती है जिसे अब अवंसर मिलेगा और वह कर्म एवं लगन से नवपंजाब की इबादत लिखेगी।” एक दशक में ही चौ. छोटूराम ने पंजाब में इस पार्टी की सरकार बनवा दी और उन्होंने अपने ग्रामीण भाइयों को यह कहना आरम्भ कर दिया कि “अब तो तुम्हें अभिमान होना चाहिए कि पंजाब में तुम्हारी सरकार हैं।” यह तुम्हारे

हित के लिए प्रतिज्ञाबद है, तुमने ही उसे बनाया है और तुम मे से तुम्हारे ही भाई उसे चला रहे हैं। पंजाब में अब सुनहरी वेला है—इतिहास इसे आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाता रहेगा।“

लोकतंत्र में जनशक्ति होती है अतएव सम्पूर्ण भारत में सुनहरी युग लाने के लिए किसान अपनी जमीदारापार्टी पुनः गठित करके किसान मसीहा चौ. छोटूराम को सच्चे श्रद्धा सुमन अर्पित करके गौरवान्वित हों। भारत में खेती, किसान और ग्राम विकास की वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है। अब किसानों में भी समृद्धि आनी चाहिए। गांव

और शहर को लेकर आर्थिक मोर्चे पर एक लड़ाई है। बहुसंख्यक जनता, जो गांव में निवास करती है मूलभूत सुविधाएं उसे भी मिलनी चाहिएं वरना गांव उज़्झते जायगें तथा सब कुछ शहरों में समा जायेगा। अतएव गांवों की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक राजनीतिक शक्ति राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी होनी जरूरी है। जिन समूहों, समुदायों, वर्गों तबकों के पास वोट की ताकत है वे अपना अधिकार मार्गेंगे ही अतः जमीदारा पार्टी का गठन होना है, सामयिक है— यही लोकतंत्र की खूबी है— वोट जिस के सरकार भी उसकी।

Collapsing Health Care System in India

- R.N. Malik

India has become a sick nation both metaphorically and otherwise. 10% population is suffering from a debilitating disease called diabetes. 14 lac new cases of cancer are reporting in various hospitals in the country every year. 1.3 lac cases of dengue and chickengunia are being reported in the Septs-Oct-November months. Government medical college Gorakhpur has become notorious for the deaths of large number of children. All Govt. and private hospitals are over crowded with patients and one gets the feeling as if whole of India has become sick. Large number of cases of paralytic strokes are reported and patients mostly go to village novices who give steroids in the garb of Ayurvedic medicines. Corridors of AIIMS (the premier All India Institute of Medical Sciences New Delhi) are so over crowded that one cannot walk without jostling others. The dates of operations are given over a period of 3 to 9 months Vitamin D deficiency syndrome has become very wide spared in urban population. Tuberculosis is taking a very heavy toll in poverty stricken areas of different states particularly in West Bengal.

The situation in States is equally alarming. In Haryana state, none of the medical colleges/Universities has the facility of conducting kidney transplantation. There is no civil hospital that has the facility for dialysis. Recently, Tribune reported that 72 PHCs are without doctors. Gurugram, a city with a population of 20 lac, has only one fully functional Civil Hospital. Even there, a team of doctors remains engaged in attending to VVIPs visiting the city quite frequently. There is a brain drain of competent doctors who take VRS and join private hospitals. Private hospitals, on the other hand, have become notorious for chagrining inflated bills by conducting un necessary tests and over charging medicines and other sundry items. Even poor people take the serious cases to private hospitals because of poor reputation of Govt. hospitals in providing medical aid. Some families have to mortgage their lands to pay for the heavy bills. The fact of the matter is that there is at least one sick person almost in every family both in rural and urban areas.

The Ministry of Health GOI or State Ministries never publish reports of epidemiological surveys showing the spread of various diseases geographically and accordingly

have failed in their duty to alarm and awaken the general public about the extent and severity of the health problems and required mitigating measures. To give one example, Shri OP Dhankhar, Minister Agriculture Haryana State stated last week that number of cancer cases coming to PGI Rohtak has increased from 5000 in 2005 to 35000 in 2012 and requested Shri JP Nadda, the Minister of Health GOI to direct AIIMS to investigate the reasons for seven fold increase. He is quoting the figures of 2012 in 2017 and why not PGI Rohtak itself do the job. Moreover this statement should have come from the Health Minister Shri Anil Vij. We rarely read any news about any break through in medical cures or treatment technologies from any medical research institute in India. So looking at this depressing scenario, everybody is scared of his medical protection or safety or security.

The basic cause of increasing incidence of afflicting diseases is that neither the Central nor the State Govts are really concerned about collapsing health services. During the recent smog in NCR. CMs of Pb, Haryana and Delhi were engaged in fierce blame games. The GOI was conspicuous by its silence. The Environment Minister was holidaying in Goa. Only Supreme Court and NGT admonished the authorities to take up some urgent remedial measures. Various causes of collapsing health care system and required remedial measures are given below.

1. Till now, there is no provision of health education at school, college and university levels. Even highly educated people do not know about the very basics of communicable and non-communicable disease. For example, how many people know that T.B. is an air born disease and a healthy person contracts this dreadful disease once a T.B patient coughs before his mouth. This educated illiteracy about health issue needs to be propelled urgently. If people are imparted the basic health education, they can take preventive measures at their own levels. Presently, the Ministries lay stress only on the curative side of health issues and neglect the prevent aspects. Therefore need of the hour is to launch an intensive and aggressive program of health education and awareness to provide nodding

- familiarity about causes and cures of common diseases afflicting the people in the country . This single step will reduce the incidents of diseases significantly.
2. There is no separate Ministry for Public Health. There is lot of difference between Ministry of Health and Ministry of Public Health in their functions. All infectious diseases and many non - infectious ones are preventable if adequate preventive measure are taken in advance. For example a town would become totally disease free (infectious ones) if every home has an access to potable water supply and sanitary latrines besides safe disposal of treated waste water and solid wastes. Disease like cholera and typhoid are totally nonexistent in developed countries simply because of availability of these facilities. In India the situation is aweful on this score, Water supply of doubtful quality / potability only is available and almost every household has installed an RO plant. Vegetables are being grown by irrigating these with sewage water under the very nose of district administration. There are hardly 10 cities in India with 100% sewerage system and sewage is rarely treated fully to the desired standards. About solid waste management plants, the least said the better.
 3. Neither the Central nor the State Governments have drawn precise roadmaps to reduce the incidents of various diseases till now. The hospital services are not fully extended to be available at a reasonable distance to the people.Primary Health Centers (PHCs) have been provided in selected villages but many villages are still without the availability of this facility. Therefore more dispensaries with qualified doctors need to be setup to cover every village or every ward. Delhi government has done a good job by setting up Mohalla Clinics to ensure availability of Primary Health Care to every household within a short radius. The governments also need to recruit adequate number of doctors and prevent their brain drain.
 4. 260 million people are leading a miserable life because of financial poverty and they have to live below the poverty line.An equal number live a notch above the poverty line and are called marginally poor. People living in these two categories invariably suffer from nutritional deficiency. Accordingly they either suffer from congenital defects or contract various diseases very easily. 52% women of child bearing age are anaemic and you can imagine the health status of new born babies in such cases. Poverty and diseases have become the two sides of the same coin. That is why poverty ridden States like U.P., Bihar, Jharkhand, M.P. and Orrisa are called five Bimarustates. To compound the issue further, population increase is maximum in these states.It is a herculean task for the government to solve this problem of malnutritionin a population chunk of 520 million persons. But Govts. have to prepare road maps to tackle this Amazonian problem.
 5. Diseases like diabetes have spread into villages because peopleno longer undergo required physical labor after the arrival of tractors and other agricultural implements like harvesters and thrashers and comparatively lead an idle mode of life. People in urban areas are contracting diseases because of extreme lack of physical activities , change in life styles and food habits, sedentary habits besides desk work in closed AC environment with reduced oxygen level in the indoor air qualityAccordingly most urbanites suffer from severe deficiency of Vitamin D which further leads to severe bone density problems (osteoporosis) . Indoor exercises in gyms do not solve this widespread problem.Human body requires a minimum amount of physical exertion to boost its healing power (generation of macrophase cells) and keep it trim and fit. Obesity is now considered as the major trigger for diabetes and cancerAccordingly an aggressive program is needed to motivate people to undergo required physical exertion .
 6. Rising air pollution in cities has become another big health hazard as inhalation of polluted air leads to incidence of many serious diseases particularly affecting the respiratory tract. Air Quality Index in NCR is close to 400 on normal days indicating a very poor quality of air. It also slows down or aggravates the healing process of other diseases already contracted by the people. 38% air pollution is due to raising of dust along the roads and remaining 62% is mostly due to vehicular exhausts. As already stated, State Govts. areleast bothered to deal with this problem. Judiciary alone can not solve this problem by issuing judicial orders/directions. Pragmatic remedial solutions are there but will power of Sate Govts. Is not there. For example, 38% air pollution caused by generation of dust can be easily controlled by paving or grassing the raw surfaces along the road edges. Vehicular pollution can be reduced enormously by restricting themovement of personal vehicles, strengthening the mass transport and construction of elevated tracks. But the question is who will bell the cat?. Only a mass movement can save the situation and that movement can be generated by an aggressive awareness program to be launched by the health ministeries.
 7. Now there is a firm belief among the people at large that human body contracts various diseases simply because of ingress of chemicals and pesticides in the food chain. Use of chemical fertilizers, pesticides and

weedicides has also killed the microbial flora and fauna of the agricultural soil. Stopping grazing activities of animals has also deprived the soil of natural replenishment of organic matter. In turn, animals too have become more vulnerable to diseases because of their reduced mobility and metabolism.

If the governments (both Central and States) decide to go into the depth of these causes and take suitable remedial measures, the health scenario in the country will present a very bright picture. In the final analysis, only key to open the doors of health safety and protection of public is preventive health care which include the activities like access to potable

water supply, total sanitary environment, health education, consumption of organic foods, required daily physical exertion, ensuring required oxygen level in AC buildings and protection from air pollution.

Kerala is one state in India which has developed a sustainable health model and has been meeting the targets of all the health indicators set by World Health Organization (WHO) since 1980. The basic feature of Kerala health Model is that the government spends more money on preventive health care than clinical or curative healthcare. It is very puzzling to observe why this model has not been adopted by other states and Government of India so far.

An Overview of Governance and Administration in India

- D.S. Hooda

In fact the most of Indians believe that the continuation of corruption has damaged our administrative, political and legal frame work to such an extent that the foundations of our polity and society have been weakened considerably. This has caused the democracy, unity and integrity of the country in danger. Hardly, there is a rare place where the corruption has not reached in one form or other.

If the country is to be liberated from corruption and mal administration, the political leaders and bureaucrats need to accept their responsibility. They are to assume leadership and play a visibly proactive role in promoting good governance. For that proximity with honest social worker and academicians is urgently required. Presently, corrupt and unlawful practices have seriously damaged the capability and credibility of Institutions of Governance.

Present election system to assembly and parliament has also damaged social fibre unity in diversity and has divided the people on religion, caste, region, etc. It has promoted 'favouritism and nepotism' in even day-to-day administration. Ironically, sometimes a candidate securing less than 20 % of total votes polled by his caste or sub-caste fellows is declared elected. Thus, it needs to be replaced by more vibrant system in which the role of these factors is mitigated to great extent.

There are countries like France, Switzerland and some more where a candidate is to secure 50% of total votes polled for winning an election to parliament and local bodies. In case no candidate secures 50%, then there will be re-polling between the two persons securing the first two positions in number of votes. The whole election will be financed by the Government. In demographical survey of India there is hardly any constituency which has more than 30% votes of one caste.

It is a matter of grave concern that in many states pliant persons of doubtful integrity are handpicked on consideration of caste, community, regions and political affiliations. Consequently, the officers and officials who are dedicated, honest and competent remains ignored and subsequently, they become frustrated and agitated. Day to day political

interference in the functioning of the Government and police machinery has resulted in unaccountability, indiscipline and loss of morale.

The people have lost trust in administration and political system due to continuously deterioration in law and order. For the last many years we have witnessed an unholy nexus between unprincipled public servants and corrupt politicians and that has created organized crimes and mafia net work. This has caused serious challenges in regard to peace and national security. Majority of youths is a spoiled lot and have addicted to drugs abuse and illicit trafficking.

Those days have gone when eminent philosophers, scientists and lawyers were chosen for the highest offices of President and Vice- President. But the recent appointments to governorships, heads of cultural institutions and national bodies have been made purely on political affiliation. Moreover, we have now become unconcerned and helpless to such things, except writing some editorials and irate columns in news papers. We have tamely adjusted ourselves to the dumping down our nation.

From any angle that you may see the present state of the nation, mediocrity is the new norm. Started by the Congress and Left, favouritism and cronyism have become now an accepted means of populating educational and cultural bodies. It is being talked that the present Government is appointing persons from the cadre of a particular cultural organization on key posts in states and centre, like, Vice Chancellors, chancellor, chairmen of IIT's and NITS, etc., ignoring more competent and experienced educationist and administrators.

It is true that despite all our chest-thumping rhetoric of alleviating poverty and illiteracy; doing away prejudices with castes, gender, region and religion; continue to remain status quo. Poverty is a curse and a black spot for the country. 34 Crore ,i.e , 26% People are still under BPL and equal number are just above the poverty line and those are called marginally poor. Thus total number of poor in India is more than the

combined population of US and Europe.

About 50% people living in villages have no roof over their heads and no means of their livelihood. No attention is being paid to the villagers about education, health, transport and employment. Consequently, they are migrating to cities and towns causing the problems of law and order, scarcity of water, shortage of electricity, crimes of theft and murder, etc.

There is absolutely need to control the bludgeoning population growing at the alarming rate. And consequently, it has become the most potential threat to the social stability of India as it will bring total anarchy to the social stability of India. It may cause explosion in the country by 2030 when all development models will fail to operate. Now even UNO has warned that population of India that India's population will be surpassing that of China by 2024.

External agencies and international terrorist groups also determined to "destabilise India by spreading religious fundamentalism, inciting conflicts and perpetrating killings". Ironically, no attention is being paid to daily violation of LOC by Pakistan army and anti national activities of youths of Kashmir. Highest attention is required to ensure that there is no lapse or deficiency in effective preservation of the country's territorial integrity.

It is a fact that states and centre are lacking in coordination to combat law and order problem and terrorism. Thus, it is crucial and important that centre and states should join hands and work together to make the life of people secure and happy. It is right time to enact a comprehensive federal law for establishing a fully empowered central agency which can take immediate cognisance and promptly investigate a terror attack anywhere in the country.

The present dispensation reminds the nation 300-400 years back in history and compels us to think and act in view of what happened in that era. People are fading up with communal violence and want to live in peace. The role of

wise people in majority determines the quality of social ties vis-a-vis minorities. But this class of persons is shrinking as it is being ignored continuously.

There cannot be two opinions that the nation is being dragged into a dangerous situation. More and more people are joining the bandwagon of narrow-minded neo-nationalist and the game of political opportunism by changing political parties and alliances.

To make India culturally strong, socially vibrant and economically buoyant the

Following Measures are suggested for urgently consideration and implementation:

- ◆ To speedily depoliticise the administration apparatus and to enforce fearlessly the rule of law
- ◆ To ensure impregnable national security management and create a country wide environment for reenergising and strengthening vital institutions of Governance
- ◆ To amend public representation act incorporating a new system of election to parliament and assemblies.
- ◆ To establish a central agency to deal with terrorism and terrorist attacks in any part of India
- ◆ To meet the most daunting challenges of reducing social and economic inequalities.
- ◆ To give proper attention to the upcoming generation by providing with gainful opportunities of employment. Their energies are appropriately channelized for reconstruction of the country.
- ◆ To control over population explosion to such an extent that one Australia is being added every year. Thus, measures of population control are urgently required for progress and prosperity of the country.
- ◆ To allocate 50% of the annual budget for villages to provide the facilities for education, health, transport and employment of rural youths.

मध्यमार्गी मन्दाकिनी ही विजयी होगी!

- डॉ. धर्मचन्द्र विद्यालंकार

भले ही इतिहास में घटनाओं का घटाटोप हो, लेकिन वह सब अकारण और अनायास कदापि नहीं है। प्रत्येक घटना-क्रम के पीछे किसी न किसी सामाजिक अथवा राजनीतिक शक्ति-संरचना का हाथ रहता ही है। यथा, राणा प्रतापसिंह का स्वतन्त्रा संघर्ष हिन्दू सामन्तशाही के पुनरुत्थान का ही उपक्रम था, तो शिवाजी मराठा का सत्ता-संघर्ष तो सीधा 'हिन्दू पद पादशाही' के लिए ही था। इसी प्रकार से औरंगजेब का धर्मान्ध शासन कट्टर इस्लामी विचार-प्रवाह ही ही तो प्रबल परिणति थी। जोकि अकबर और जहाँगीर एवं शाहजहाँ की समन्वयशील और उदार राजनीति की ही प्रखर प्रतिक्रिया थी। जिसमें मुल्ला-मौलियों को अपने अन्ध-धर्मदेशों को निरीह और निस्सहाय जनता पर आरोपित करने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। लगभग वही मनःस्थिति हिन्दू धर्म के पोंगा-पण्डितों की भी थी।

अतएव मध्ययुगीन इतिहास में भी हम तीन प्रकार का वैचारिक संघर्ष राजनीतिक क्षितिज पर देख सकते हैं। यदि एक हिन्दु पुनरुत्थानवादी धर्मधारा थी तो दूसरी प्रतिक्रिया स्वरूप कट्टर इस्लामी या बहाबी विचारधारा थी जोकि सूफी-संतों की वहदत अथवा अद्वैतवाद के दूसरे छोर पर खड़ी थी। जबकि मुस्लिम और हिन्दू संत, पीर और फकीर मानव-मात्र की एकता और समानता का ही स्वर-घोष सतत भाव से कर रहे थे। 'एक ही पहचानिये अस मानुष की जात'। यही तो नानक और कबीर ने कहा था।

हिन्दू पुनरुत्थानवादी और कट्टर इस्लामिक बाहवी विचार-प्रवाह के मध्य में अन्तः सलिला सरस्वती के समान वही मध्यमार्गी विचार-परम्परा अविरल भाव से अनवरत प्रवाहित थी। जब-जब भी भारत की राजनीति की धुरी अपने इस अक्ष से इधर-उधर विचलित

होती है; तभी यहाँ पर उथल-पुथल मचती रही है। साम्प्रदायिक इंज्ञावात उठते रहते हैं और अलगाव की आँधियाँ चलती रही हैं। जब जब भी भारतीय राजनीति मध्य मार्ग गामी रही हैं; तभी वह सुरसरी के समान मन्द-मन्दगामी और अप्रतिहत आवेग के साथ बहती रही है। पूरे के पूरे मध्यकाल का इतिहास हस्तामूलकवृत् हमारी आँखों के सामने है।

यह कहावत प्रसिद्ध है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है, या पुनरावृत्त करता है। भारतीय स्वतन्त्रा-संग्राम में भी हम उपर्युक्त विद्यारा, सिद्धान्त को समाहित देख सकते हैं। यदि एक कट्टर इस्लामी बहावी विचार-परम्परा प्रतिक्रियास्वरूप प्रगतिशील परन्तु शोषणक्षम आंगूल साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्षत थी, तो इसी प्रकार से एक कट्टर हिन्दू सामन्तशाही को पुर्णजीवित करने वाली विचार-परम्परा भी मराठा-सामन्तों के नेतृत्व में संघर्ष-सन्नद्ध थी। जोकि धर्मगत भेदभावों के चलते ही प्रथम स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय हुई थी। लेकिन इन दोनों ही पुरातन पंथी और प्रतिगामी विचार-प्रवाहों के मध्य में भी एक किसान और मजदूरों की मध्यवर्ती विचारधारा थी जोकि बजाय धर्मगत कारणों के आर्थिक विषमतावर्धक कारकों की प्रतिक्रियास्वरूप उद्भेदित और आन्दोलित हुई थी।

इसीलिए तो संभवतः डॉ० रामविलास शर्मा जैसे सुधी समालोचक ने प्रथम स्वात्र संघर्ष में बजाय समझौतावादी और सुविधाजीवी सामन्तों को संघर्ष का श्रेय देने के उन्होंने 'वर्दीधारी किसानों' को ही सच्चा बीर सिपाही ठहराया है। क्योंकि वे बिना किसी प्रकार धर्मिक और जातीय विद्वेष भाव के विशुद्ध राष्ट्रप्रेम की भव्य भावना से ही ओतप्रोत और आप्लावित थे। जनज्वार का विशुद्ध जल-प्लावन अथवा सही सैलाब वही था। जोकि बढ़े हुए भारी भरकम भूराजस्व और राज्यतंत्र में व्याप्त नस्लीय भेदभाव के ही विरुद्ध वक्ष तान कर खड़े हो गये थे। भले ही उनका नेतृत्व सामन्ती सन्नायकों ने किया हो, लेकिन भारत-माता के वही सच्चे सैनिक सपूत थे। क्योंकि वे किसी वैचारिक अतिवाद से ओतप्रोत नहीं थे, बल्कि जनधारा ही उनकी एकमात्र विचारधारा थी जोकि स्वयं में मध्यमार्गीय ही थी।

यदि हम इससे भी आगे बढ़कर बीसर्वों शताब्दी में चलने वाले स्वतन्त्रा-संघर्ष को देखते हैं तो उसमें भी यह त्रिविध विचार-विमर्श स्पष्टतः दिखाई पड़ता है। यदि मुस्लिम लीग 'निजामे-मुस्तफा' के नाम पर पुनः इस्लामी साम्राज्य-स्थापन के स्वर्णिम स्वप्न संजो रही थी; तो हिन्दू महासभा भी उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप हिन्दू पदपादशाही के सुनहरी सपने देख रही थी। लेकिन एक समन्वयशील मध्यवर्ती अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसी विचारधारा भी थी जोकि इन सारे ही विचार-विवर्तों को अपने अमल आवेग में अन्तसमाहित करके चल रही थी। जिसका नेतृत्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पं० जवाहरलाल नेहरू ने किया था।

जहाँ पर हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही धर्मधाराएँ भारतीय जन-समाज को मध्ययुगीन कुहासे की ओर पुनः प्रतिनिवृत्त करना चाहती थी; यह मध्यमार्गी विचार-प्रवाह अग्रगामी और दूरदर्शी था। जिसकी दूर-दृष्टि भारत के उज्जवल भावी क्षितिज पर टिकी हुई थी। वह स्वयं में आधुनिक और उन्नतिशील अथवा पुरोगामी भी थी। वह कोई मध्यकाल का यूटोपिया अथवा कल्पित कल्पना-लोक नहीं रचना

चाहती थी, धार्मिक आधार पर। अपितु परलोक की बजाय इहलोक को ही स्वर्ग-सोपान बनाने की अटूट विश्वासी थी। जबकि कालबाह्य धर्मधाराएँ हमें हमारे अंधकारयुगीन अतीत में भी उज्जवल आलोक की अनुभूति कराना चाहती थी।

इस मध्यमार्गी समन्वयशील विचार-परम्परा ने भारतवर्ष की सामाजिक 'गंगा-यमुना' संस्कृति को सहजभाव से स्वीकार किया था। बजाय दो कौमों अथवा राष्ट्रों के समग्र भारतवर्ष को एक और अखण्ड-अक्षुण्ण रखने के लिए समस्त देशवासियों को एक ही रक्त-वंश के वंशज माना। उनकी एक सांझी ऐतिहासिक विरासत को सहर्ष स्वीकार किया। तुर्कों और मुगलों एवं अफगान शासकों को भी बजाय विधर्मी और विदेशी के स्वदेशी स्वीकारा। तभी एक जातीयता और राष्ट्रीयता का नव-निर्माण हुआ था। अतएव हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही मतावलम्बियों ने कंधे से कंधा मिलाकर एक विदेशी और शोषक शासन-सत्ता के विरुद्ध सुरीघ संघर्ष किया था। तभी जाकर कहाँ हमें स्वतन्त्र वायु में श्वास लेने का यह स्वर्णिम अवसर सुलभ हुआ है। जबकि दोनों ही अतिवादी धर्मधाराएँ भारतवासियों को परस्पर में ही धर्म के नाम पर लड़ा-भिड़ाकर दुर्बल बना रही थी। यही नहीं, वे हमारी दासता को और भी अधिक चिरंजीवी कर रही थी।

आजकल एक बार पुनः भारतीय राजनीति के प्रस्तर-पटल पर वही पुराने विचार-विवर्त उठ रहे हैं। भारत-विभाजन के पश्चात इस्लामी बहावी धर्मधारा तो कुछ कमज़ोर पड़ गई है क्योंकि मुस्लिम बहुल प्रदेश भारतीय भूभाग से विच्छिन्न होकर पृथक् देशः पाकिस्तान में चला गया है। लेकिन भारत-विभाजन की उसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अपनी सनातन धर्मधारा की सत्ता-संस्थापना का आधार हमारे कुछ पोंगांपंथी और प्रतिगामी धर्मधर्वजी बनाना चाहते हैं। जब हमने यह पूर्व में ही निश्चित कर लिया था कि जो इस देश को अपना देश नहीं मानते और जो धार्मिक आधार पर राष्ट्र का विभाजन चाहते हैं, वे पाकिस्तान चले जाएँ, और ऐसा मानने और सोचने वाले यहाँ से स्वेच्छापूर्वक अथवा अनिच्छापूर्वक प्रस्थान भी कर गये। तब हमने अपने संविधान में यह शपथ ली थी कि यह भारत एक धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक राष्ट्र रहेगा। तथापि आजकल एक दक्षिणमार्गी विचार-धारा उस सबल संकल्पना से पीछे क्यों हटना चाहती है।

यदि हम इसी प्रकार से जातीय अथवा धार्मिक आधारों पर समाज का विखण्डन करेंगे तो स्वयं हिन्दू-समाज में भी असंब्य अन्तर्विभाजन हो जायेंगे। क्योंकि उसमें सैकड़ों मत-पंथ हैं तो सहस्रों जातियाँ और उपजातियाँ हैं। हिन्दू समाज स्वयं में कोई एकाशम संरचना नहीं है। वह बहुधर्मी और बहु-नस्लीय है। अतएव इन भेदों और प्रभेदों के चलते स्वयं उसके अपने अन्तर्विरोध उभरकर सतह पर आ जायेंगे। क्योंकि कहीं पर सर्वण हैं तो कहीं पर अन्त्यज और शूद्र तथा दलित जातियाँ हैं। कहीं पर पिछडे किसान हैं तो कहीं पर आदिवासी अस्मिताएँ भी हैं। अतएव नाना रूपाकारी अनेकता विद्यमान हैं।

अब भारतीय राजनीतिक धरातल पर प्रमुखतः तीन या चार ही विचार-परम्पराएँ प्रवाहित हो रही हैं। जिनमें से यदि एक प्रतिक्रियावादी हिन्दूवादी दक्षिणपंथी धर्मधृत राजनीति हैं; तो दूसरे छोर पर धर्म-पंथ का

निःशेषतः: निःशेष करने वाली वाममार्गीय राजनीति हैं। जोकि धर्म और पंथ को राजनीति के लिए विष के समान विषम व विभाजनकारी मानती है। तीसरे छोर पर एक दलित या अम्बेदकरवादी विचार-परम्परा भी है जोकि हिन्दू धर्म की वर्ण-व्यवस्था वाली सोपानिक अथवा क्रमिक असमानता वाली संरचना के धुर विरोध में खड़ी है। यह विचारधारा हिन्दू समाज के श्रमिक-शूद्रों को वर्ण-व्यवस्था की विषमता-वर्धक सामाजिक संरचना के मुक्ति दिलाकर उन्हें समानता के समतल धरातल पर लाना चाहती है। हमें ऐसे प्रतीत होता है कि भारतीय स्वर्णसमाज की पाचन-क्षमता अत्यन्त विशाल है। उसका अगाध उदर बाहरी रूप से उदर भी है; अतएव ‘हिन्दू धर्म की एकता’ के नाम पर वही सनातनी या उनकी अपनी दृष्टि में यही सड़तनी धर्मधारा उसे अन्तर्भुक्त अपने अगम्य उदर में कर लेगी।

बीर बाला भोली व उसके गांव लजवाना की वीर गाथा

— रामशरण

महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए आज देश में खूब प्रयास किए जा रहे हैं। देश की राजनीती में ‘महिला आरक्षण’ को लेकर भले ही द्यामासान चल रहा हो, किन्तु हमारे देश के लोग यह भूल रहे हैं कि इस देश को आजाद कराने, गुलामी के लिए कुर्बानी पुरुषों ने दी है, उसमें महिलाओं की भागीदारी भी कम नहीं है।

इस श्रेणी में हरियाणा की वीर-बाला ‘भोली’ का नाम एक सीमीत क्षेत्र में ही चर्चित होकर रह गया है। रियासत जीन्द के गांव लजवाना की इस वीर बाला ने वर्ष 1854 के युद्ध में जीन्द नरेश महाराजा सरूप सिंह की सेना के दांत खट्टे करके एक ही दिन में 16 सिपाही मौत के द्याट उतार दिए थे।

यह द्यटना सन् 1854 की है, जब जीन्द के महाराजा सरूप सिंह के एक तहसीलदार लाला कौर सेन (कंवर सेना) लजवाना के समीपवर्ती गांव ढीगाना में लगे दरबार में लोगों से गाली-गलौज सहित अभद्र व्यवहार पर उतर आये। गांव लजवाना के नम्बरदार भूरा व निगाईया आपस में घोर विरोधी होते हुए भी यह सहन नहीं कर पाए और गांव में वापस आते समय इन दोनों ने रास्ते में आपस में मंत्रणा करके राजा के विरुद्ध संदर्भ की योजना बना डाली। शाम को ही गांव की आमसभा करके, गांव की ओर से राजा के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर डाली। योजना के अनुसार अगले दिन जब तहसीलदार कौर सेन और उसके अमले के आदमी गांव की पास (चौपाल) में पहुंचे तो इस अवसर पर भूरा व निगाईयां नम्बरदार को वहां उपस्थित न देखकर उन्हें तुरन्त हाजिर करने का हुक्म दे डाला। गांव के कुछ नौजवान, जो इस अवसर की ताक में थे, तहसीलदार कौर सेन पर टूट पड़े। तहसीलदार ने चौपाल की पिछली खिड़की से भागने की कोशिश की, परन्तु गांव वालों ने उसे मारकर गांव के बाहर कालीदेवी के मन्दिर के पास उपलों में डालकर जला डाला।

कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जब तहसीलदार कौर सेन चौपाल के पिछले दरवाजे से भागने लगा तो एक युवा-लड़की

दूसरे छोर पर रही साम्यवादी राजनीतिक चिन्तन-दृष्टि जोकि पूर्णतया पंथ अथवा धर्म-निरपेक्ष है। उसको अधार्मिक और नास्तिक अथवा धर्मद्वारा ही और देशद्वारा ही बताकर मुख्यधारा ने परिधि पर पटक दिया है। अतएव ले-देकर हमारे सम्मुख वही मध्यमार्गी कांग्रेसी एकमात्र राष्ट्रीय विचार-परम्परा अवशिष्ट रहती है। जोकि सारे धार्मिक और जातिगत भेदभाव से ऊपर उठाकर भारतीय समाज और राष्ट्र को एक और अखण्ड रख सकती है। आजकल वर्चस्ववादी सनातनी विचार-परम्परा सत्ता के शिखर पर है, अतएव वही प्रबलता के साथ प्रभुत्व प्राप्त भी है। यह जलप्लावन की भाँति शैलप्रवाही प्रतीत हो रही है। लेकिन शैल-शिखर से अवतरित होकर समतल मैदानों में आकर वही मध्यमार्गी मन्दाकिनी विचारधारा पुनः प्रवाहित होगी। यही हमारा अविचल और अटूट विश्वास है।

ने चौपाल का पिछला दरवाजा बन्द कर तहसीलदार को भागने से रोक दिया। गांव के एक युवक ने गण्डासे से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस लड़की का नाम ‘भोली’ बताया गया है। यह लड़की नवयुवकों के साथ ही रहकर मार-काट के कार्यों में भागीदार रहती थी।

इस घटना की सूचना राजा सरूप के पास पहुंची तो राजा ने दोनों नम्बरदारों को तलब किया। परन्तु गांव की ओर से जवाब भेजा गया – ‘सारा गांव दोषी है, इसलिए किसी को भी पेश करना कठिन है।’ राजा की ओर से फिर प्रस्ताव पहुंचा – ‘यदि सारा गांव सामूहिक रूप से माफी मांग ले तो मामला निपटाया जा सकता है, परन्तु ग्रामवासियों ने इसका कोई भी उत्तर न देकर चुपी सी साध ली। कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर राजा जीन्द ने अपने सेनापति मेजर अली को गांव पर हमला करके सबको खत्म करने का हुक्म दे दिया। उधर गांव वालों ने भी राजा से मुकाबला करने कर तैयारी की ली। गांव की रक्षा करने के लिए सारे प्रबंध कर लिए गए। सारे गांव के ईर्द-गिर्द मिट्टी की बड़ी-बड़ी दीवारें बना दी और गांव के चारों ओर खाइयां खोद दी गई, खन्दकों सभी प्रकार से मोर्चे तैयार कर लिए गए।

राजा की फौज ने गावों पर तोपें से धावा बोल दिया। परन्तु लोगों ने भूरा व निगाईया की कमान में आक्रमण का मुंहतोड जवाब दिया तथा वीरता से गांव की डटकर रक्षा की। यह संदर्भ लंबे समय चला। कुछ दिनों के बाद महाराजा ने देखा कि गांव वालों का जोर है, तो उसने रियासत नाभा और पटियाला के सासकों से सहायता की प्रार्थना की। तीनों राज्यों की फौजों ने एक साथ चढ़ाई की, परन्तु गांव फिर भी नहीं टूटा और गांववासियों ने से गांव की रक्षा की। यह लडाई पूरे छह मास तक चली अन्ततः राजा द्वारा अपने अंग्रेज सरकार से सहायता मांगे स्थिति को भांपकर, गांववालों के गांव को छोड़कर चले जाने अपनी भलाई समझी। इस युद्ध के कारनामों को आज भी

भाट लोक गीतों में वीरगाथा के रूप में गाते हैं। 'लजवाना लडाई' नाम की इस गाथा को जोगी व भाट घरों-घरों वीर रस में लोगों को मन्त्र मुध कर देते हैं।

कहते हैं कि इस युद्ध में गावों की एक युवा लड़की जिसका नाम 'भोली' बताया जाता है, ने भी अद्भुत वीरता दिखाई उसने एक ही दिन में 16 रियासती सिपाही मौत के द्याट उतार दिए थे जिससे दुश्मन की फौज में भगदड मच गई। उसकी गाथा आज भी बच्चे-बच्चे की जुबान पर है। इस वीरांग साहस से प्रेरित होकर ही गांव के लड़ाकुओं में अथाह/उत्साह का संचार हो पाया था और वह जी-जान से रियासती फौजे से लंबे समय तक लड़ते रहे।

विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि उस समय औरत ऊपर कड़े सामाजिक प्रतिबंध थे। लेकिन उस युद्ध में भोली ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। भोली ने अपने भाई के युद्धमें मारे जाने का समाचार सुनकर ग्रामीण के मना करने के बावजुद सिर पे कफन बांध के उस पर पहचं कर रियासत सेना से जा भिड़ी। अपनी काली ओढ़नी (टुपड़े) पगड़ी की तरह बांधकर उसने दुश्मनों की सेना पर कल्पे आम कर दिया था। एक ही दिन में 16 रियासती सैनिकों को मारकर

कीर्तिमान स्थापित कर दिया। आस-पास के गावों में आज उसके बारे में यह दो बोल प्रचलित हैं:-

'सेर बाजरा झोली में,
सोलह काट्ये भौली नैं।'

आज भी लजवाना की याद आते ही जीन्द की ग्रामीण महिला यह बड़े दर्द से गाती हैं:-

'...लिजवाने तेरा नाश जाइयों,
तनैं पुत बड़े खपाये।'

ऐतिहासिक पुस्तकों में चाहे अब तक इन घटनाओं को विस्तार से जगह न मिली हो, लेकिन हरियाणा निवासित इनकी वीरता की मिसालें आज भी ताजा हैं। भूरा व निगाई के साथ-साथ भोली का नाम भी अमर हो गया है। इनकी वीरता का जिक्र आते ही लोग कह उठते हैं:-

'जो जन्म इस कालरी में,
मर्द बड़ा हड्डखाया,
गोला बांट्या गोबर का,
लजवाना गाम बरोबर का।'

बॉयोटेकनोलॉजी क्षेत्र में लाखों नौकरियों के अवसर

- अनामिको

देश की बॉयोटेक इंडस्ट्री पिछले चार वर्षों में ढाई गुना से ज्यादा बढ़ी है। इसमें सबसे बड़ा कारण बायोफार्म सेक्टर का विस्तार है। अलग-अलग सेक्टरों में बढ़ते विस्तार से युवाओं के लिए नौकरियों की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इस इंडस्ट्री में 2020 तक हर साल 3 लाख से ज्यादा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अधिक जानकारी के लिये ये पढ़े रोचक लेख।

बॉयोलॉजी और टेक्नोलॉजी के सम्मिलित रूप को बॉयोटेकनोलॉजी कहा जाता है। यह साइंस की ब्रांच है, जिसमें विषयों की भरपूर विविधता देखने को मिलती है। इसमें जेनेटिक्स, बॉयोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी, केमिस्ट्री, और इंजीनियरिंग के साथ मेडिकल व हेल्थ साइंसें विषय भी शामिल हैं। इसका उपयोग सैल बॉयोलॉजी से लेकर, क्रॉप स्टैटिस्टिक्स और सॉइल कंजर्वेशन जैसे क्षेत्रों तक में भी होता है। हाल के वर्षों में तकनीक के विस्तार से इस इंडस्ट्रीमें तेजी देखने को मिली है। इसके कारण इसमें प्रोफेशनलज की मांग भी बढ़ी है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में 2020 तक सालाना 30 लाख से ज्यादा नौकरियों के अवसर होंगे।

देश की बॉयोटेक इंडस्ट्री 2015 में करीब 7 अरब डॉलर की थी जो 30 फीसदी की दर से बढ़कर 2025 तक करीब 100 अरब डॉलर होने की संभावना है। दुनिया के शीर्ष 12 बायोटेक बाजार में से एक भारत भी है। देश की बायोटेक इंडस्ट्री की विश्वभर के बायोटेक इंडस्ट्री बाजार में 2 फीसदी हिस्सेदार है।

देश की बॉयोटेकनोलॉजी इंडस्ट्री में आज करीब 800 कंपनियां हैं। इनकी कमाई में सबसे बड़ी हिस्सेदारी बॉयोफार्म और बायोसर्विसेस की है। वहीं केंद्र सरकार के साथ-साथ विभिन्न राज्यों द्वारा भी इंडस्ट्री के विकास के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। इससे इस क्षेत्र में जॉब के नए अवसर बनेंगे।

बॉयोटेकनोलॉजी के क्षेत्र में कई प्रकार के काम होते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की दवाईयां, वैक्सीन, उत्पादन क्षमता बढ़ाना, एनर्जी प्रोडक्शन और कंजर्वेशन आदि का काम किया जाता है। इसका उपयोग एनिमल ब्रीडिंग और एनिमल हस्बैंड्री में भी किया जाता है। बॉयोटेकनोलॉजिस्ट का काम लिविंग ऑर्गेनिज्म या उत्पादों को विकसित करना और इसका उपयोग करके स्वास्थ्य और वातावरण को बेहतर बनाना है।

सांइंस बैग्राउंड वाले बना सकते हैं कैरियर फिजिक्स केमिस्ट्री और बॉयोलॉजी या मैथ्य से बाहरीं करने वाले छात्र बॉयोटेकनोलॉजी से संबंधित कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। बैलचर स्तर पर बॉयोटेकनोलॉजी के बीएससी, बीटेक और कई कोर्स कराए जाते हैं। इसके बीड या बीटेक कोर्स में प्रवेश के लिए जेर्झी मेन का वैलिड स्कोर जरूरी होता है। इसके अलावा छात्र इसके बीएससी कोर्स में भी प्रवेश ले सकते हैं। इसमें प्रवेश के लिए संस्थानों द्वारा खुद का एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करया जाता है। अधिकांश संस्थानों में प्रवेश के लिए 12वीं में कम से कम 50 फीसदी अंक जरूरी होते हैं। बॉयोलॉजिकल सांइंस से संबंधित विषयों जैसे बायोकेमिस्ट्री, बॉयोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी, वेटरनरी के मास्टर से बैचलर डिग्री

करने वाले छात्र बॉयोटेक्नोलॉजी के मास्टर डिग्री में प्रवेश के योग्य हैं। पोस्टग्रेजुएट स्तर पर इसके एमटेक और एमएससी कोर्स कराए जाते हैं। रिसर्च या एकेडमिक्स के क्षेत्र में कैरिअर बनाने

के लिए छात्र इसका पीएचडी कोर्स भी कर सकते हैं।

रिसर्च लैब में जॉब की अच्छी संभावनाएं

बॉयोटेक्नोलॉजी फार्मास्युटिकल कंपनियों, केमिकल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और इससे संबंधित इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। उनके लिए एग्रीकल्चर और एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में भी नौकरियों के अवसर हैं। ये प्रोफेशनल बायो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में प्लानिंग, प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के क्षेत्र में जॉब कर सकते हैं। हालांकि इसमें जॉब की ज्यादा संभावनाएं सरकारी और प्राइवेट लैबोरटरीज में होती हैं। इसके अलावा बायोटेक से

संबंधित कंपनियों जैसे फूड मैन्यूफैकर और एक्वाकल्चर आदि में नौकरी कर सकते हैं।

शुरुआत में ही 20–25 हजार रुपय प्रति माह का पैकेज

बायोटेक इंडस्ट्री में प्रोफेशनल की मांग पिछले कुछ वर्षों में ही तेजी से बढ़ी है। इसमें फेशर को 20 से 25 हजार रुपय प्रति माह की सैलरी मिलने की संभावना होती है। हालांकि बड़े संस्थानों से पासआउट छात्रों को शुरुआत में ही अच्छा पैकेज मिलता है। आईआईटी जैसे संस्थानों से पास होने के बाद छात्रों को 60 से 80 हजार रुपय प्रति माह का शुरुआत पैकेज मिल सकता है। शिक्षण संस्थानों में काम करने वालों को भी शुरुआत में 30 से 35 हजार रुपय प्रति माह की सैलरी मिलने की संभावना होती है।

(दै. भास्कर से साभार)

क्या अण्डा शाकाहार है?

बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत सारे अण्डों का प्रयोग करते हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो डाक्टर कहते हैं कि अण्डा खाने से ताकत मिलती है और शरीर को प्रोटीन की पूर्ति होती है। शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए अण्डा खाना अच्छा रहता है। दूसरी बात यह भी है कि अण्डा शाकाहार में आता है। दोनों बातों पर विचार कर लेना चाहिए।

मानव शरीर को प्रोटीन अन्य पोषक तत्वों की जो आवश्यकता होती है वह अन्य शाकाहारी भोजन से पूरी हो जाती है। जहाँ तक प्रोटीन का सम्बन्ध है वह दालों से, दूध से व सूखे मेवों जैसे बादाम, मूंगफली आदि से मिल जाती है। ताकत देने वाले खाद्य पदार्थों में दूध, घी, बादाम, अखरोट, काजू आदि आते हैं। तो ताकत व प्रोटीन के लिए हमें अण्डे की कहाँ आवश्यकता हुई? यदि यह कहा जो कि अण्डे वाली प्रोटीन विशेष लाभकारी है तो फिर जो व्यक्ति अण्डे का सेवन नहीं करते, उनके शरीर को यह विशेष प्रोटीन कहाँ से मिलती है। क्या वे ताकतवर व स्वस्थ नहीं होते? तो हम अण्डे के बिना स्वस्थ व ताकतवर रह सकते हैं तो अण्डे का औचित्य क्या हुआ?

दूसरी बात कही जाती है कि अण्डा शाकाहार में आता है तो इस बारे में बातों पर विचार करना आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि यदि अण्डे को खाने की अपेक्षा यदि मूर्गी के पास छोड़ दिया जाये तो पांच-छह दिन बाद अण्डे से चूजा निकलेगा। इसका मतलब हुआ अण्डा मूर्गी का भ्रूण हुआ और अण्डा खाना भ्रूण हत्या हुई, जो कि मांसाहार श्रेणी में आता है। यदि यह कहा जाए कि अब ऐसे अण्डे भी होते हैं जिनमें चूजे नहीं निकलते तो ऐसे अण्डे खाना तो शाकाहार में आयेगा।

यहाँ जो भी पदार्थ है (दाल, अनाज, सब्जी, फल, दूध) सभी में कार्बोहाईड्रेट अनिवार्य रूप से मिलेगा। मांसाहार (मांस, मछली, अण्डे) में केवल प्रोटीन व वसा ही होती है। अब शाकाहारी भोजन में कार्बोहाईड्रेट होता नहीं और अण्डे की तरह मांस व मछली में भी कार्बोहाईड्रेट नहीं होता तो आप अण्डे को शाकाहार में कैसे रख सकते हो। इसलिए अण्डा शाकाहार में न आकर मांसाहार में आता है। दूसरे मांसाहार में अण्डे में भी रुक्षांश (रिशा तत्व) बिल्कुल नहीं होता और रुक्षांश पाचन तन्त्र को साफ रखने के लिये आवश्यक होता है तो अण्डे का भोजन पाचन तन्त्र को ठीक से साफ नहीं होने देता और आन्तों में दुर्घन्द पैदा करता है और पाचन सम्बन्धी विकार पैदा करता है। हमें अण्डे के सेवन से बचना चाहिये।

आवश्यक सूचना

जाट सभा चण्डीगढ़/पंचकूला द्वारा जनवरी 2018 से समय-समय पर जनहित में “परिवार परिचय सम्मेलन” का आयोजन शुरू किया जायेगा जिसमें विवाह योग्य युवक-युवतियों का पारस्परिक परिचय कराया जायेगा। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले युवक-युवतियों व उनके माता-पिता/अभिभावकों के लिये भवन परिसर में रात्रि विश्राम व खाने की व्यवस्था भी की जायेगी।

आप सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम के सफल व भली-भाति आयोजन के लिये अपने विचार व सुझाव जाट भवन, 2-बी, सैक्टर-27 ए, चण्डीगढ़ व सर छोटूराम जाट भवन सैक्टर-6, पंचकूला में भेजने का कष्ट करें।

वैवाहिक विज्ञापन

- ◆ SM4 Jat Girl (DOB 31.05. 90) 27.7/5'6" B.Tech. (Textile Technology), PIET, Samalkha (gold medalist in 2011.) GATE qualified, M. Tech (Fashion Technology) BVSMV, Khanpur Kalan (gold medalist) 2014. Employed as Assistant Professor PIET, Samalkha since August 2014. Avoid Gotras: Malik, Hooda, Chahal, Pahal. Cont.: 09717484982
- ◆ SM4 Jat Girl (DOB 19. 07. 90) 27.5/5'4" M.A., M.Phil, Ph.D, NET, HTET, PGT Test cleared. Avoid Gotras: Duhan, Sehrawat, Kundu. Cont.: 09416620245
- ◆ SM4 Jat Girl (DOB 4.5.90) 27.7/5'3" M.C.A., B.Ed. (Math) Doing math tuitions. Avoid Gotras: Sangwan, Faugat, Dangi. Cont.: 09813776961
- ◆ SM4 Jat Girl 27/5'4" B.Tech EEE. Working in MNC at NOIDA. Avoid Gotras: Berwal, Nain, Kataria, Rathee. Cont.: 08708561731
- ◆ SM4 Jat Girl (DOB March 89) 28.6/5'3" MCA from P.U. Employed in Punjab & Haryana High Court. Avoid Gotras: Sheoran, Punia, Sangwan. Cont.: 09988359360
- ◆ SM4 Jat Girl 26/5'3" MBA, Working in MNC Gurgaon with 11 LPA. Father Class one officer/E.D. Chandigarh. Preferred Civil Service/ IIT, IIM, MNC/PCS boy. Avoid Gotras: Dhaka, Lodayan, Phalswal. Cont.: 09530994232
- ◆ SM4 Jat Girl (DOB 24.07.89) 28.5/5'5" B.Com (Hons.) CS, PGDBA, MBA, Working as Company Secretary in a reputed company at Chandigarh. Avoid Gotras: Gahlawat, Jakhar, Ola. Cont.: 09464741686
- ◆ SM4 Jat Girl 27/5'2" B.A. JBT, Pursuing MA. Avoid Gotras: Lakra, Dahiya, Gulia. Cont.: 08930821521, 0130-2285030
- ◆ SM4 Jat Girl (DOB 28.11.93) 24/5'2" Graduation from P.U. and doing MA from P.U. Avoid Gotras: Beniwal, Sejwal, Kadian, Kuhad, Kaliraman. Cont.: 08699378476
- ◆ SM4 Jat Girl (DOB 02.03.93) 24.7/5'2" Passed Staff Nurse (GNM) Course. Employed in a reputed hospital at Zirakpur. Avoid Gotras: Doriwal, Lakhlan, Beniwal. Cont.: 09023265894
- ◆ SM4 employed Jat Girl (DOB August 1991) 26/5'2" B.Com, MBA, B.Ed. Knows car driving. Father retired, mother teacher. Avoid Gotras: Malik, Lohan. Cont.: 09416367647, 09416203233
- ◆ SM4 Jat Girl (DOB 01.06.89) 28.4/5'3" M.Sc. Bio-technology from P.U. Doing Ph.D. Avoid Gotras: Tomar, Chhikara. Cont.: 09991192846
- ◆ SM4 Jat Girl (DOB 04.05.90) 27.5/5'3" MCA, B.Ed. Maths. Avoid Gotras: Sangwan, Phogat, Dangi. Cont.: 09813776961
- ◆ SM4 Jat Girl (DOB 08.09.91) 26/5'5" BA, Doing HRM. Father Army Officer. Avoid Gotras: Malik, Rathi, Pawar. Cont.: 08146962977
- ◆ SM4 Jat Girl (DOB 26.07.94) 23.3/5'5" B. Tech, Doing MBA. Father Army Officer. Avoid Gotras: Malik, Rathi, Pawar. Cont.: 08146962977
- ◆ SM4 Jat Girl 24/5'8" M.A. English Knowledge of Short Hand Typing. Avoid Gotras: Malik, Sangwan, Dahiya. Cont.: 09217884178
- ◆ SM4 Jat Girl (DOB 10.05.84) 23.5/5'2" B.P.T. Employed as Physiotherapist in Semi-Govt. Hospital at Panchkula. Avoid Gotras: Bains, Durka. Cont.: 09815078800, 09882249898
- ◆ SM4 Jat Girl (DOB 23.12.91) 25.10/5'4" B.Com. Hons, MBA Employed as P.O. in ICICI Bank Pune. Avoid Gotras: Bijarnia, Jakhar. Cont.: 09023093808
- ◆ SM4 Jat Girl (DOB 13.09.92) 25/5'3" B.Sc (Computer Science), M.Sc math with Computer Science from MDU.Rohtak, B.Ed. from Punjabi University. Father is Block Officer in Forest Deptt. at Pinjore. Avoid Gotras: Jatain, Dahiya, Dhattarwal. Cont.: 08901273699
- ◆ SM4 Jat Girl 27/5'3" B.Com, MBA (Finance) Employed in MNC, Mohali. Avoid Gotras: Saroha, Phaugat, Sehrawat. Cont.: 09888462399
- ◆ SM4 Jat Girl 27/5'7" BDS, Pursuing for MDS, Father Retired Army Officer. Avoid Gotras: Narwal, Mor, Kadyan. Cont.: 08556074464
- ◆ SM4 Jat Girl DOB (18.10.84) 33/5'3" B.Com, M.Com from Kurukshetra University, Computer Course in Financial Accounting & Honours Diploma in Computer Application. Doing job as Accountant of Share Market (BSE) at Panchkula. Avoid Gotras: Kadian, Malik, Khatri. Cont.: 09468089442, 08427098277
- ◆ SM4 Jat Girl DOB 1990 27/5'7" Post Graduate, Employed at Chandigarh. Only well settled family with urban background, preferably in Tricity. Avoid Gotras: Khatkar, Malik. Cont.: 09888626559
- ◆ SM4 Jat Girl (DOB 29.06.90) 27/5'3" Graduated from Shri Ram College of Commerce, Delhi. Employed as India Brand Manager for Swift in Maruti India Pvt. Ltd. Delhi. Earning 14 LPA. Family settled at Panchkula. Avoid Gotras: Rathee, Dahiya, Lamba. Cont.: 09988099453
- ◆ SM4 Jat Girl (DOB 18.08.88) 29/5'3.6" M.Sc. Math, B.Ed. Working in a reputed private School. Avoid Gotras: Bankura, Mann, Narwal. Cont.: 09354839881
- ◆ SM4 Jat Girl (DOB 13.06.90) 27/5'2" B.Tech (CSE) Employed as Assistant in Central Excise Department at Chennai. Avoid Gotras: Malik, Hooda, Joon. Cont.: 09780336094
- ◆ SM4 Jat Girl (DOB 08.11.90) 26.10/5'3" Employed as Staff Nurse in Government Hospital, Sector 6, Panchkula. Avoid Gotras: Dahiya, Kajla, Ahlawat. Cont.: 09463881657
- ◆ SM4 Jat Girl (DOB 13.10.91) 25.10/5'5" B.A. LLB, (Hons) LLM, Pursuing Ph.D from M.D.U. Rohtak. Advocate in Punjab & Haryana High Court. No dowry seeker. Preferred match Chandigarh, Panchkula. Avoid Gotras: Malik, Deswal. Cont.: 09417333298
- ◆ SM4 Jat Girl (DOB March 1990) 27.5/5'7" Convent educated, Post Graduate, Employed, Highly educated family. Please contact only well educated family. Tcicity (around Chandigarh) based family preferred. Avoid Gotras: Sura, Malik. Cont.: 09888626559
- ◆ SM4 working Jat Girl 26/5'3" BPT, MPT, CMT, Employed as Consultant Chyisiotherapy in private hospital in Panchkula. Avoid Gotras: Chhikara, Dahiya, Bajar. Cont.: 09467680428
- ◆ SM4 Jat Girl (DOB 02.12.91) 25.8/5'5" M.Com, B.Ed. Employed as teacher in a private school at Zirakpur with Rs. 16000/- PM. Avoid Gotras: Kadyan, Jakhar, Malik. Cont.: 09815098264
- ◆ SM4 Jat Girl (DOB 21.04.88) 28.3/5'1" M.Tech from P.U. Chandigarh, GATE cleared. Avoid Gotras: Dhull, Goyat, Bhal.

- Cont.: 09467671451
- ◆ SM4 working Jat Girl 24.6/5'7" B.Tech, MBA, Preference Defence Officer. Avoid Gotras: Chhikara, Chhillar, Dalal, Tomar, Shokeen. Cont.: 09313662383, 09313433046
- ◆ SM4 Jat Girl (DOB 23.10.87) 29.8/5'5" B.Com, MBA, MIS, M.A (Economics.) Avoid Gotras: Panghal, Baloda, Bhaghasra. Cont.: 09463967847, 09463969302
- ◆ SM4 Jat Girl(DOB 07.02.90) 26.10/5'10" B.Tech (ESE) M.Tech (ESE) from MDU Rohtak. GATE qualified. Avoid Gotras: Kadian, Rathee, Sangwan. Cont.: 08447796371
- ◆ SM4 Jat Girl 26/5'5" B.D.S. Employed in Parexel Company in I.T. Park Chandigarh. Family settled at Chandigarh. Tri-city match preferred. Avoid Gotras: Kundu, Malik, Sandhu. Cont.: 09779721521
- ◆ SM4 Jat Boy (DOB 20.09.88) 29/5'11" I.I.T (Delhi) MBA from XLRI Jamshedpur. Working in Private sector. Father professor in M.D.U. Rohtak. Preferred well qualified, hardworking, ambitious match. Avoid Gotras: Malik, Dahiya. Cont.: 08084028112
- ◆ SM4 Jat Boy 27/5'10" Employed as Auditor-CAG at Itanagar. Avoid Gotras: Sehrawat, Ahlawat, Phogat. Cont.: 09215641283
- ◆ SM4 Jat Boy (Divorced-no issue) 38/5'9" MSc. Statistics from H.A.U. Hisar, Employed in Franklin Tempton Investment Company Hyderabad with Rs. 38 LPA. Avoid Gotras: Sheoran, Bachhal. Cont.: 09416271636
- ◆ SM4 Jat Boy 25/6' B.Com, Doing M. com Employed in Central Post Office at Chandigarh. Family settled at Chandigarh. Preferred match in Govt. job. Avoid Gotras: Kundu, Malik, Sandhu. Cont.: 09779721521
- ◆ SM4 Jat Boy 29/5'11" MBA Employed in South Africe with 18 Lak package. Avoid Gotras: Lakra, Dahiya, Gulia. Cont.: 08930821521
- ◆ SM4 Jat Boy 27/5'10" Matric passed, Deaf & Dumb Doing private job. Avoid Gotras: Beniwal, Kadian, Dhankhar. Cont.: 09255479697, 09996840080
- ◆ SM4 Jat Boy 26/6'2" B.Tech (Computer Science) Employed in I.T. Company (Presto) at Mohali with Rs. 6 lakh Package. Avoid Gotras: Bhanwala, Antil, Grewal. Cont.: 09466188502
- ◆ SM4 Jat Boy 28/5'10" Employed as Service Engineer in TATA Motors at Narela (Delhi). Avoid Gotras: Kundu, Malik, Rathee. Cont.: 08950092430
- ◆ SM4 Jat Boy (DOB 14.11.92) 25/6' B.E. (Mechanical) Employed in BALCO (Bharat Alumy) KORBA as Assistant Manager. Father working as Junior Executive BALCO, Mother housewife. Only son. Avoid Gotras: Jhajariya, Pawadia, Jhanuwa. Cont.: 09416206610
- ◆ SM4 Jat Boy (DOB13.10.86) 31/6' B.Tech (ECE) Employed in Punjab Judicial Department. Avoid Gotras: Siwach, Dahiya, Suhag. Cont.: 09988005272
- ◆ SM4 Jat Boy (DOB 05.06.88) 29.2/5'11" Employed as Computer Programmer in Food & Supply Deptt. Kaithal. Family settled in Kaithal. Six acre Agriculture land. Avoid Gotras: Ravish, Sheoran, Badu, Kala. Cont.: 09729867676
- ◆ SM4 Jat Boy 28/5'8" LLB, Practising Advocate, Own house, plot, flat, 3 acre agriculture land. Father Senior Advocate. Avoid Gotras: Balyan, Nehra. Cont.: 09996844340, 09416914340

- ◆ SM4 Jat Boy (DOB 16.08.88) 29/5'10" MA (Public Admn.) Employed as Govt. JBT Teacher at Panchkula. Avoid Gotras: Dhillon, Siwach, Swag. Cont.: 09417424260
- ◆ SM4 Jat Boy (DOB1882)35/5'9" M. A. (Eng.) M.A Mass Communications, M.Phil mass communications and Ph.D mass communications from K.U.K. Working as Deputy Chief Reporter in Dainik Jagran with Rs.35000/- P.M. Father ex-serviceman, mother retired teacher. Avoid Gotras: Malik, Gahlawat. Cont.: 09416616144, 08901447789
- ◆ SM4 Jat Boy (DOB 25.12.91) 25.6/6'2" Employed as J.E. in Corporation Panchkula. Avoid Gotras: Malik, Vigay, Rajan. Cont.: 0172-4185373
- ◆ SM4 Jat Boy 29/5'11" Employed as team leader in IT Park Chandigarh with Rs. 8 lakh package PA. Avoid Gotras: Khatri, Ohlyan, Rathee. Cont.: 09833286255, 09468463165
- ◆ SM4 Jat Boy (DOB13.08.89) 27/5'10" B. Tech. from India, M.Tech from Canada. Doing Job in TRONTO (Canada). PR status. Avoid Gotras: Sarao, Basiana, Ojaula. Cont.: 08288853030
- ◆ SM4 Jat Boy (DOB13.08.89) 31.7/6'1" MA, Mass Communications from London. Working in MNC Gurgaon with 12.5 lakh package PA. Avoid Gotras: Dahiya, Ahlawat. Cont.: 09717616149
- ◆ SM4 Jat Boy 30/5'9" B.Tech, MBA (UK) Marketing Manager, 60 lacks PA. Avoid Gotras: Tomar, Poriya. Cont.: 09412834119
- ◆ SM4 Jat Boy 30/5'10" MBA, Working in MNC, CTC 14Lpa, Preferred B.Tech, MBA/Lecturer. Avoid Gotras: Panwar, Kadian, Dalal. Cont.: 09810280462
- ◆ SM4 Jat Boy (DOB 30.09.89) 27.6/5'10" B. Tech. Computer Engineering. Two flats and one showroom in Gurgaon. Father retired Principal. Avoid Gotras: Sheokand, Malik, Punia. Cont.: 09871044862
- ◆ SM4 Jat Boy (DOB 28.10.85) 31.4/5'11" MBBS, M.S. from PGI Rohtak. Posted at Bhalot (Rohtak) as regular Medical Officer. Preference M.D., MBBS match. Avoid Gotras: Malik, Phogat, Antil. Cont.: 09416770274
- ◆ SM4 Jat Boy (DOB 28.10.90) 26.10/5'11" BDS, MDS. Father S.D.O. retired from Haryana Government. Avoid Gotras: Malik, Phogat, Antil. Cont.: 09416770274
- ◆ SM4 Jat Boy (DOB 01.08.85) 31.6/6'1" M.A., Mass Communication from London (England). Employed in MNC Company at Gurgaon with Rs. 12.50 Lakh Package PA. Avoid Gotras: Dahiya, Ahlawat. Cont.: 09717616149
- ◆ SM4 Jat Boy (DOB Nov.1989) 27.1/6' B.Sc in Hospitality & Hotel Administration. Occupation Hotel Industries in Dubai, Package Rs.10 lakh P.A. Father, Mother Haryana Govt. Employees at Panchkula. Avoid Gotras: Kundu, Dahiya, Tomar (Not direct Sangwan, Bhanwala) Cont.: 09416272188, 09560022263
- ◆ SM4 Jat Girl 22/5'4", M.Com, Doing B.Ed for, Avoid Gotra : Chahal, Sheokand, Mosa. Cont.: 9468407521
- ◆ SM4 Jat Girl 28/5'3", Qufilation PGDCA, working as cleark, Hry Civil Secretaray. Avoid Gotra : Chahal, Sheokand, Mosa. Cont.: 9468407521
- ◆ SM4 Jat Girl (DOB: 18.08.89) 28/5'3", B.Tech, M.A. English, working as PGT. Avoid Gotra : Nain, Sangwan, Dhanda. Cont.: 9417196763

जीवन से सीख

स्नान के बाद अर्ध्य देते हुए पंडितजी बुद्बुदा रहे थे—‘प्रीति बड़ी माता की और भाई बल। ज्योती बड़ी किरणों की और गंगा का जल।’ यह सुनकर वहां ये गुजर रही बुजुर्ग महिला हस पड़ी। पंडितजी को उसका हसना अपमानजनक लगा। उन्होंने सरपंच से शिकायत कर दी। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। सरपंच ने महिला से कहा—‘तुमने पंडितजी का अपमान क्यों किया।’ पंडितजी बोले—‘कल तुम हंसी थी, वह मेरा अपमान नहीं था ?

महिला ने जवाब दिया—‘आप पर नहीं, आपकी बात सुनकर हंसी थी।’ पंडितजी बोले—‘मैंने कहा था—प्रीति बड़ी माता की और भाई का बल। ज्योती बड़ी किरणों की और गंगा का जल।’ सरपंच ने कहा—‘इसमें हंसनें की बात क्या है ?’ महिला बोली—पंडितजी की बात सत्य प्रतीत

होती है, पर है नहीं ’ सरपंच ने पूछा—‘तो किर सत्य क्या है ?’ महिला ने कहा—‘प्रीति बड़ी त्रिया की और बाहों का बल। ज्योती बड़ी नैनों की और मैঘোं का जल। बात अगर पिता और पुत्र में फंसे तो मां पुत्र का साथ नहीं देगी, लेकिन पत्नी हर हाल में साथ होगी। जब बैरी अकेले में घेर लेगा तो भाई का नहीं, अपनी बाहों का बल काम आएगा। ज्योती नैनों की इसलिए बड़ी है कि जब आखे ही न हो तो सूरज की किरणों की रोशनी या अमावस का अधेरा सब बराबर है। गंगाजी पवित्र है, लेकिन वे मैঘों के समान न तो जन-जन की प्यास बुझा सकती है न सिंचाई कर सकती है। पंडितजी से कहा—‘अब आप क्या कहेंगे ?’ पंडितजी बोले—‘मैं समझ गया, किताबी ज्ञान काफी, नहीं है। जीवन से भी सीखना होगा।

जाटों के लिए आचार संहिता

जाट एक स्वाभिमानी पंथनिरपेक्ष कौम है। आज हमें एक मजबूत संगठन की आवश्यकता है। जिले, प्रदेश व राष्ट्र स्तर पर नई दिल्ली जाट संस्थाये/समायें अपने—अपने प्रभाव क्षेत्रों में समाज कल्याण के कार्य करते आ रहे हैं—कर रहे हैं। लेकिन इन सभी प्रयासों की एक सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्रीय स्तर का एक मजबूत संगठन बनान समय की एक पुकार है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के चारों तरफ जाट बाहुल्य क्षेत्र मौजूद हैं। दिल्ली हमारी जमीन पर बसी है लेकिन दिल्ली में हमारी शक्ति का केन्द्र कोई सामाजिक स्थान—भवन आदि नहीं है जहां से कौम का मार्गदर्शन किया जा सके। दिल्ली में गूजर भवन है, यादव भवन है, विश्नाई भवन है, यहां तक कि दक्षिण भारतीयों के भी अपने—अपने संगठन—भवन आदि दिल्ली में भवन हैं परन्तु जाट भवन का दिल्ली में न होना हमारी कमजोरी का घोतक है। इस तेज तर्रर तकनीकी युग में हमें सुशिक्षित, सुव्यवस्थित एवं संगठित हो कर आगे बढ़ने की जरूरत है। इस संदर्भ में श्री जिले सिंह सहरावत द्वारा प्रस्तावित) जाट आचार संहिता। (ब्कम वि ब्वदकनबज वित श्रंजे) पर विचार—विमर्श करना समाज हित में आपके सुझाव, संशोधन सादर आमंत्रित हैं।)

प्रस्तावित आचार संहिता का प्रारूप मजबूत संगठन का आधार

1. जाट संगठित हों और हमारा संगठन मजबूत हो ताकि यदि कोई व्यक्ति समाजहिताके विरुद्ध कार्य करता है तो उसके खिलाफ फतवा आदि दिया जा सके ताकि उसे यह महसूस हो कि उसने गलत कार्य करके समाज की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाई है।
2. प्रत्येक जाट संगठन अपना संविधान बनाए और वह पंजीकृत

हों। संविधान के अनुसार ही सब कार्यवाही की जायें क्योंकि संविधान समाज को शक्ति प्रदान करता है, जिससे संगठन को मजबूती मिलती है।

3. समाज संबंधी विषयों पर मिल बैठ कर विचार विमर्श करे और बहुमत के आधार पर ही कोई निर्णय लें। इससे संगठन मजबूत होगा।
4. आपसी मतभेद/विवाद को कोर्ट कचहरी में ना जाकर सामाजिक पंचायती स्तर पर ही सुलझाने की चेष्टा करे।
5. अपने समाज में पूर्ण रूप से प्रजातंत्र प्रणाली का प्रयोग करें इससे संगठन की शक्ति बढ़ेगी।
6. प्रत्येक जाट शिक्षित हो, अनुशासित हो, और दूसरों के अनुभवों से लाभ उठाने वाला हो।
7. हम सामाजिक कुरितियों का बहिष्कार करें। नशे से दूर रहें, रुद्धिवादिता का त्याग करें बुरी संगत से बचे। अच्छी संगत धारण करते हुए सभी धर्मों का आदर करें।
8. विवाह—शादी में दहेज न लें, न दें और फिजूल खर्चा व दिखावें से बचे।
9. एक सफल जाट परिवार अपने क्षेत्र के दूसरे जाट परिवारों को भी सफल होने का रास्ता दिखाए, उनकी हर प्रकार से सहायता करे, अर्थात अपने कल्याण के साथ—साथ अपने भाईयों का भी कल्याण करें।
10. मन्दिर आदि की अपेक्षा दान—दक्षिणा अपने जाट संस्थानों की उन्नति के लिए देना अधिक उचित होगा।
11. अपना भविष्याव लक्ष्य निर्धारित करें और फिर उसी दिशा में मेहनत करके सफलता हासिल करें।

12. समय की गति के अनुसार बदलते रहें नहीं तो दुनिया की दौड़ में पिछे रह जायेंगे अर्थात् अपनी मान-मर्यादा को समय अनुसार सुधारते रहे।
13. कोई भी संकट अज्ञान व दुर्बलता से उत्पन्न होता है। इसलिए उपयुक्त शिक्षा पा कर ज्ञानी बनें और सात्त्विक उत्तम भोजन द्वारा बलवान बनें। फिर किसी भी संकट का सामना करने में आप सबल होंगे।
14. नारी का मान-सम्मान करना सिखें और सभी कार्यों में स्त्री को बराबर का स्थान दें। आज हमारी बहु-बेटियां सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। यदि बेटियों को बेटों की भाँति पाला-पोसा जाए तो वे और भी उत्साहजनक कार्य कर सकती हैं।
15. अंधविश्वास को त्याग कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनायें।
16. जाट लंगोट का पक्का ओर चरित्रवान हो।
17. किसी भी क्षेत्र में अपने किसी भाई-बहन को सफल होते देखकर इर्ष्या न करें अपितु उस सफल व्यक्ति का अनुसरण करके लाभान्वित हों।
18. खुद अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें और बच्चों को महापुरुषों की जीवनियाँ आदि पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करें।
19. आलस्य को त्यागों और अपने लक्ष्य की ओर चलें और चलते रहें जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो।
20. सफलता पर प्रसन्न तो हों परन्तु गर्व (घमंड) न करें। सफलता के सफर में सहयोग/सहायता देने वालों को न भूलें।
21. अपने श्रम, ज्ञान, स्वाभिमान, ईमानदारी, सदाचारिता व आत्मविश्वास से समाज को समृद्ध व शक्तिशाली बनाने में भरसक योगदान दें।
22. दृढ़ संकल्प एवं मजबूत इच्छाशक्ति वाले बनें।
23. छोटो पर दया और बड़ों व वृद्धजन्नों का मान-सम्मान करें। उनके अनुभवों का लाभ उठायें।
24. कर्मयोगी और प्राक्रमी बनें तथा देवी-देवताओं पर भरोसा कम करें।
25. जिद्दी हठी न बनकर विनिम्र और विचारशील बनें।
26. स्वार्थ त्याग कर सदाचारी बनें और समाज के कार्यों में यथाशक्ति हाथ बढ़ायें।
27. जाट मृदुभाषी हो लेकिन उस की भुजाएँ प्राक्रमी और मजबूत हों।
28. विरोधियों को नष्ट करने की न सोचकर मध्यर भाषा और सहानुभूति आचरण से उन की विचार धारा बदलने की चेष्ठा करें। अर्थात् शत्रु को भी अपना मित्र बनाने का प्रत्ययन करें।
29. आलस्यहीन, उत्साही, बहादुर, धर्मनिरपेक्ष और मित्रता निभाने वाले बनें।
30. सहनशील बनें व दूसरों के विचारों, मान्यताओं का आदर करें, यहीं पुरानी सर्वखाप पंचायतों की परम्परा रही है।

भलाई पर स्थापित हो जीवन व्यवस्था

— प्रो. अख्तरुल वासे

को सदैव पुण्य जाना गया।

सामूहिक जीवन के अच्छे तथा बुरे मामलों में भी मानवता का फैसला सर्वमान्य ही रहा है। सम्मान का पात्र सदैव वह समाज रहा है जिसमें वयवस्था हो, आपसी सहायता तथा सहयोग हो, आपसी प्यार तथा एक दूसरे के लिये शुभ चिंतन हो, सामूहिक न्याय तथा सामाजिक समानता हो, दुर्योगस्था, कृप्रबंध, उंच-नीच, भेदभाव, असमानता, अन्याय तथा अत्याचार को कभी सामूहिक जीवन के लिए उचित नहीं गिना गया।

मानवीय नैतिकता वह सर्वव्यापी एवं अंतराष्ट्रीय हकीकते हैं जिनको सभी जानते हैं और सदैव से जानते चले आ रहे हैं। पाप एवं पुण्य कोई छुपी हुई वस्तुएं नहीं हैं। वे तो मानवता की जानी-पहचानी वस्तुएं हैं, जिनका ज्ञान मनुष्य की प्रकृति में रखा गया है। सही कारण है कि कुरान अपनी भाषा में पुण्य को 'मारूफ' तथा पाप को 'मुनकर' के शब्द से याद करता है। अर्थात् पुण्य वह है जिसे सभी मनुष्य भला जाने और पाप वह जिसे सभी बुरा समझें।

इस्लामी नैतिक व्यवस्था का आधार ईश्वर, संसार तथा मनुष्य संबंधी वे धारणाएं हैं जो इस्लामी आस्थानुसार मनुष्य को दिए गए हैं। इस्लाम ऐसी जीवन व्यवस्था की मांग करता है जो भलाई पर स्थापित हों। उसका निमंत्रण यही है कि जिन भलाइयों को मानवता ने सदैव से भला जाना हैं आओ उन्हें स्थापित करें।

भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी चलता हैं जाटों का रुतबा

दैनिक हिन्दुस्तान समाचार पत्र में कुछ समय पहले जातियों की लोकतंत्र नामक एक लेख श्रृंखला प्रकाशित की गई। इसकी 13वीं एवं आखिरी किस्त में जाटों पर छपे लेख में रोचक तथ्य प्रस्तुत किये गये। पाठकों के ज्ञानवर्धन हेतु अरविन्द मोहन द्वारा लिखित इस लेख को 'जाट लहर' में साभार प्रकाशित किया जा रहा है।

उत्तर भारत की राजनीति में अपने कद से भी ज्यादा प्रभाव डालने वाली जातियों में जाटों का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन उनके रुझान से स्पष्ट है कि राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली में उनके बोट एकजुट होकर नहीं पड़ते। उनके बोटों में बदलाव रहता है। जाटों में सबसे बड़े जमावड़े वाले राजस्थान में उनका रुझान पहले की तुलना में भाजपा की तरफ ज्यादा रहा है। अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी उनके नेताओं व जनता का रुझान भाजपा की तरफ लगता है।

जाटों में राजनैतिक चेतना और बिरादरी—भाव नया नहीं है। स्वभावतः वे केन्द्र में विरोधी भी रहे हैं। उनके बीच हुए सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह जब सर छोटूराम के जमाने में अविभाजित पंजाब को अपने स्वजातिय लोगों को कांग्रेस की तरफ लाने का प्रयास कर रहे थे तब जाटों का, खास कर बड़े जर्मींदार जाटों का रुझान अंग्रेजी हूकुमत के पक्ष में था। चौ. चरण सिंह का जमाना आने में साठ के दशक का इंतजार करना पड़ा। हरियाणा के जाटों में राजनैतिक चेतना पंडित भगवतदयाल शर्मा के कथित ब्राह्मणवाद की प्रतिक्रिया के रूप में पैदा हुई। आजादी से पहले राजस्थान के आम जाटों को तो वहां के राजे—रजवाड़े पगड़ी पहनने और घोड़ी चढ़ने पर रोक लगाए हुए थे। वैसे कुछ जाट रजवाड़े भी थे।

राजस्थान में जाटों की संख्या सबसे अच्छी है। एक बार जब उनके अपने बोट का महत्व पता चला तो सारे दल लाईन लगाकर उनके पीछे पड़ गए। यहां पहले चौधरी देवीलाल, फिर ओमप्रकाश चौटाला और उनके पुत्रों ने सीधे दखल दी तो चौधरी चरण सिंह ने भी अपनी राजनीति में राजस्थान को पर्याप्त महत्व दिया। लेकिन ये प्रभाव हाशिए पर रहे। इस दौर के नेता नाथुराम मिर्धा, कुंभाराम आर्य और एक हद तक राम निवास मिर्धा भी अपनी अलग राजनीति करने से रुकते नहीं थे। पर जब एक बार जाटों में आरक्षण का सवाल राजस्थान राज्य की राजनीति के केन्द्र में आया तो भाजपा ने उसका सर्वाधिक लाभ लिया। आरक्षण भले ही अशोक गहलोत की कांग्रेसी सरकार के सौजन्य से मिला पर उसका राजनैतिक लाभ भाजपा को मिला। इसकी एक बड़ी वजह विधानसभा चुनाव में वंसुधंरा सिंधिया को आगे करना भी है जो जाट राज परिवार में ब्याही है।

विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस इस सवाल पर चौकस

हुई। इसी बिरादरी के नेता को प्रदेश की बागड़ेर सौंप कर उसने टिकटों में भी जाटों का खास ख्याल रखा। असल में 25 में से 19 सीटों पर 10 फीसदी से ज्यादा आबादी वाली जाट जाति की अपेक्षा अब संभव नहीं है। राजस्थान राज्य की ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र में जाटों का हिस्सा 12 फीसदी है जबकि 7 चुनाव क्षेत्रों पर तो उनका बड़ा दबदबा है। सीकर, नागौर, चुरू, बीकानेर, जोधपुर, झुझानू, गंगानगर वगैरह में तो उनकी आबादी 20 फीसदी से भी ज्यादा है।

इस हिसाब से उत्तरप्रदेश में जाटों की आबादी कम है। अविभाजित उत्तर प्रदेश में उनका हिस्सा सिर्फ दो फीसदी माना जाता था। पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश भर में सीमित होने और आर्थिक—सामाजिक—राजनैतिक चेतना में सबसे ऊपर होने के चलते जाट समुदाय यहां पर सबसे ज्यादा असर डालता रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का संकेंद्रण हुआ है और यहां की तरह सीटों पर 6—7 से लेकर 14 फीसदी तक उनकी आबादी मानी जाती है। इसी आधार पर चौधरी चरण सिंह ने निरंतर सत्ता में रहने का लाभ उठाया। लेकिन उनके पुत्र चौधरी अजीत सिंह अपने विरासत में कमज़ोर पड़ते गए। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जाट बोटों का रुझान—रुझान भाजपा की तरफ मुड़ता नजर आता है।

हरियाणा प्रदेश में 12 में से 10 सीटों पर जाटों की आबादी 20 से 40 फीसदी तक मानी जाती है। सोनीपत, सिरसा, रोहतक, हिसार और भिवानी में तो इस बिरादरी के बोट 40 फीसदी तक हैं। इसलिए हरियाणा की राजनीति का असली सूत्रधार जाट ही है। वर्तमान में जाट समुदाय का रुझान भाजपा की तरफ नजर आता है, और इसी कारण इस बार हरियाणा में भाजपा सरकार बनी।

वैसे तो मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, और ग्वालियर तथा उत्तराखण्ड के हरिद्वार जैसी सीटों पर भी जाटों की आबादी ठीक ठाक हैं, पर इन राज्यों में या सीटों पर जाट निर्णायक नहीं हैं। लेकिन जब 45 से 50 संसदीय सीटों का मामला हो और जाट बिरादरी अपनी संख्या से ज्यादा अनुमान में राजनैतिक सत्ता लेती रही हो तो स्वाभाविक है कि बोटों के सही सौदागर इस बिरादरी के आगे दंडवत करते नजर आएंगे। उल्लेखनीय है कि जाट सिर्फ हिन्दुओं में ही नहीं सिक्खों और मुसलमानों में भी हैं। पंजाब में अगर जाट सिक्खों का रुतबा है तो पूरा पाकिस्तान जाट मुसलमानों का लोहा मानता है। वहां पर पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री रहे चौधरी परवेज इलाही जाट हैं। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद रफीक तरार भी जाट हैं। उन्होंने संयुक्त पंजाब के शासक चौ. छोटूराम से वजीफा पाकर शिक्षा प्राप्त की थी। "इंडस सागा" नामक पुस्तक के लेखक एडवोकेट एवं पाकिस्तान के पूर्व मंत्री एहतजाज एहसन भी जाट हैं।

सम्पादक मंडल

संरक्षक : डा. एम.एस. मलिक, आई.पी.एस. (सेवानिवृत)

सम्पादक : श्री गुरनाम सिंह, आई.एफ.एस. (सेवानिवृत)

सह—सम्पादक : डा. राजवन्तीमान

साज सज्जा एवं आमुख : श्री आर. के. मलिक

प्रकाशन समिति : श्री बी.एस. गिल, मो० : 9888004417

श्री जे.एस. ढिल्लो, मो० : 9416282798

वितरक : श्री प्रेम सिंह, कार्यालय सचिव, जाट भवन, चंडीगढ़

जाट भवन 2—बी, सैक्टर 27—ए, चंडीगढ़

फोन : 0172—2654932 फैक्स : 0172—2641127

Email : jat_sabha@yahoo.com

Postal Registration No. CHD/0107/2018-2020

RNI No. CHABIL/2000/3469